सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 14, नई दिल्ली, मंगलवार, 08 नवम्बर 2022, पेज 8

NEWS TRANSPORT VISHESH NTV
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 राजधानी में इन वाहनों पर अभी भी जारी रहेगा बैन
05 अगले साल तक हो सकता यामहा इलेक्ट्रिक स्कूटर का दीदार
08 दक्षिण भारत को 11 नवंबर को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन

आज का सुविचार

ज़िन्दगी बदलने के लिए
लड़ना पड़ता है,
आसान करने के लिए
समझना पड़ता।।

ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निवास पर किया भारी प्रदर्शन

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की दमनकारी नीतियों और प्रदूषण की आड़ मैं टैक्सी बस वालो को बेरोजगार करने की साजिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली के किया दिल्ली के मुख्यमंत्री खिलाफ रोष प्रकट

- पर्यावरण मंत्री हम गरीब टैक्सी वालो और टेम्पो ट्रैवेलर वालो के साथ दोहरा रवैया अपना रहे : संजय सम्राट

संजय बाटला

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की दमनकारी नीतियों और प्रदूषण की आड़ मैं टैक्सी बस वालो को बेरोजगार करने की साजिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली के मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल के निवास पर भारी प्रदर्शन किया. बेशक़ आज कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने स्टेज 4 को आंशिक रूप से हटा दिया लेकिन पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने और AQI की मात्रा कम होने के बावजूद डीजल की यूरो 4 की सारी प्राइवेट कारो /टैक्सीयों और टेम्पो ट्रेवलर को दिल्ली एनसीआर में बंद करने का फरमान जारी कर दिया.

टैक्सी एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय जी ने प्रदूषण में सुधार को देखकर और AQI की मात्रा कम होने पर हलके मालवाहक ट्रक और बड़े ट्रको की एंट्री भी दिल्ली में खोल लेकिन हमारी यूरो 4 डीजल की टैक्सीयों और टेम्पो ट्रैवेलर को चलाने से बंद कार दिया. एक तरह से पर्यावरण मंत्री जी ने हम गरीब टैक्सी वालो और टेम्पो ट्रैवेलर वालो के साथ दोहरा रवैया अपना रहें हे. जो की सरासर गलत हे.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन करके मांग की थी अभी और भविष्य में दिल्ली सरकार हमारी डीजल की यूरो 4 टैक्सी -टेम्पो ट्रेवलर को बंद ना करें और अगर करें भी तो अभी और भविष्य में हमारी गाड़ियों को रोकने का मुआवाजा दे.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हे की दिल्ली सरकार ने जिस तरह दिल्ली के टैक्सी वालो और ट्रांसपोर्टर्स की डीजल की गाड़ियाँ बंद करने की साजिश करके टैक्सी वालो को बर्बाद करने की साजिश रची हे दिल्ली की सरकार को MCD के इलेक्शन में इसकी कीमत चुकानी होंगी क्योंकि MCD के इलेक्शन सर पर हे.

कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मिली भगत इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कम्पनी से हे इस की पूरी सभावना हे ? क्योंकि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही हे जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम गाड़ियों से 100% से 300 % तक महंगी हे, इनकी रख रखाव भी आम गाड़ियों से 10 गुना महंगा हे और भविष्य में अगर इन गाड़ियों की एक बैटरी भी खराब हो जाए तो एक बैटरी की कीमत भी कम से कम एक लाख रुपय के आसपास होती, और गाड़ियों में काफी बैटरी होती हे,

श्री गोपाल राय जी ने स्कूल खोल दिए सब कुछ खोला पर हमारी डीजल गाड़ियों को रोक कार सरकार दोहरा रवैया अपना रही हे, क्योंकि दिल्ली सरकार के परिवहन बिभाग के इनफ़ोर्समेंट विभाग में सारी इन्नोवा गाड़ियाँ यूरो 4 डीजल की हे, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में जो गाड़ियाँ मंत्रियो की सिक्योरिटी में लगी हे वो भी सारी यूरो 4 डीजल की हे.

पंजाब और दुसरे राज्यों में पराली जलाना दिल्ली सरकार से रोका नहीं जा रहा हे जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी की पार्टी की पंजाब में सरकार हे.

संजय सम्राट का कहना हे की दिल्ली सरकार को सिर्फ प्रदूषण हमारी गाड़ियों में नजर आ रहा हे जबकि हर साल हम दिल्ली के परिवहन विभाग से प्रदूषण सर्टिफिकेट लेते हे जिस से साबित होता हे की हमारी गाड़ियाँ प्रदूषण नहीं फैलाती, हर 2 सालो में हमारी डीजल गाड़ियों की फिटनेस होती हे जिसमे प्रदूषण सर्टिफिकेट के हर साल हम 120 रुपए और कुछ गाड़ियों के हर 3 महीने में 120 रुपए देते हे फिटनेस के हर गाडी की 10 हजार रुपए जिसमे दिल्ली सरकार ने पेनिक बटन के नाम पर पहले ही अरबो रुपए का घोटाला कर रखा हे जिसकी शिकायत हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से की थी और इस घोटाले की जांच की मांग सीबीआई द्वारा कराने की

टैक्सी एसोसिएशन ने अरविन्द केजरीवाल जी के घर पर प्रदर्शन करके मांग की अभी और भविष्य में

दिल्ली सरकार हमारी डीजल की गाड़िया बंद ना करें.

इसके अलावा हमारी कुछ डीजल गाड़ियों के चालान हुए. जिसमे 20 हजार ड्राइवर का चालान और 20 हजार गाडी मालिक का और 2000 का अलग से चालान ट्रैफिक पुलिस ने किया हे. इनको माफ़ करने की भी हमने मांग की हे

हम अपनी मांगो का ज्ञापन मुख्य मंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी को सौपा हे.

संजय सम्राट ने बताया कि आज हम प्रदूषण की वजह दुसरे राज्यों मैं पराली जलाना हैं. जो प्रदूषण का मुख्य कारण हैं. या कंस्ट्रक्शन या फिर बड़ी फैक्ट्रीयों का धुआं. या फिर कूड़े के पहाड़ो को जलाना.

और सबसे बड़ी सच्चाई ये हैं की मौसम जब सर्दी का आता हैं तो थोड़ा बदलाव तो मौसम मैं होता ही हे लेकिन दिल्ली सरकार इन बातो का फायदा उठाकर टैक्सी टेम्पो ट्रेवलर वालो को बेरोजगार करने पर तुली हैं

संजय सम्राट का कहना हैं की दिल्ली सरकार हर किसी को मुआवजा या सब्सिडी देती हैं. जैसे बिजली, पानी, सवास्थ्य, महिलाओ को बस में फ्री टिकट, वकीलों को 5 लाख का हेल्थ बीमा फ्री और भी काफी सहूलियत. लेकिन हम टैक्सी -बसों और टेम्पो ट्रेवलर वालो को कोई सहूलियत नहीं

भविष्य में हम भी दिल्ली सरकार का साथ देने को तैयार हैं. हम अपनी सारी गाडी पार्किंग मैं खड़ी कर देंगे लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार हम टैक्सी बस वालो को इसका मुआवाजा दे.

टेम्पो ट्रेवलर के 6000 एक दिन के

इन्नोवा किरस्टा के 5000 एक दिन के

स्विफ्ट दीजयर ईटिंओस के 4000 एक दिन के दे

दिल्ली सरकार हमें ये पैसा रोज के हिसाब से हर गाडी के हिसाब से अभी और भविष्य में दे.

और या फिर अभी और भविष्य में

फिर हमारी डीजल गाड़ियों को कभी ना रोके

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी हे की डीजल गाड़ियों से बैन हटाया जाए क्योंकि वो प्रदूषण नहीं फैलाती. अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दिल्ली के रोड जाम कार देंगे.

संजय सम्राट ने ये भी कहा हे की सुप्रीम कोर्ट ने डीजल की गाड़ियों को 10 मई 2016 में बंद कर दिया था लेकिन बाद में फिर दिल्ली सरकार ने यूरो 4 डीजल टैक्सीयों के रजिस्ट्रेशन करें और करोडो रूपए हमसे टैक्स के रूप में लिए.

इनसाइड

लखनऊ मेट्रो को मिला उत्कृष्टता का पुरस्कार

लखनऊ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ मेट्रो में सफर कर रहे हैं। लखनऊ के लिए गर्व की बात है कि आपकी मेट्रो को देश में शहरी परिवहन के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला। चार से छह नवंबर के बीच कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन-2022 में उत्कृष्ट शहरी परिवहन के लिए पुरस्कार दिया गया। 'मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी-माडल इंटीग्रेशन' की श्रेणी में मेट्रो का चुनाव किया गया है। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार को केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया। समारोह में महानिदेशक परिचालन स्वदेश सिंह भी मौजूद थे। सम्मेलन में देश भर के शहरी परिवहन निकाय की ओर से हर वर्ष हिस्सा लिया जाता है। लखनऊ मेट्रो को देश भर में उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। इसके लिए मिला पुरस्कार : मल्टी-माडल इंटीग्रेशन के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसका अर्थ है कि लखनऊ मेट्रो स्टेशनों को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे के साथ ही सबसे बेहतर तरीके से शहर के रेलवे स्टेशनों बस स्टैंडों जैसे अन्य परिवहन टर्मिनलों के साथ जोड़ा गया है।

नवंबर महीने के पहले पांच दिनों में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि पाई गई

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। वर्तमान नवंबर महीने के पहले पांच दिनों में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि पाई गई है। उदाहरण के लिए, कल यानी 5 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 2817 मामले सामने आए, जबकि राजस्थान में 91, हरियाणा में 90 और उत्तर प्रदेश में 24 मामले सामने आए। किसी एक दिन में सबसे अधिक आग के मामले 2 नवंबर को दर्ज किए गए, जब खेतों में पराली जलाने के मामले पंजाब में सबसे अधिक 3,634 और राजस्थान में यह संख्या 63 तक दर्ज की गई थी।

पंजाब में नवंबर के पहले पांच दिनों में पराली जलाने के मामलों में असामान्य वृद्धि पूरी तरह से हवा की गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में लाने के लिए जिम्मेदार है।

पंजाब में 1 से 5 नवंबर, 2022 तक पराली जलाने की 13,396 घटनाएं दर्ज की, जबकि अक्टूबर, 2022 के पूरे महीने में यह संख्या 16,004 थी। नवंबर में खेतों में पराली जलाने के मामलों की संख्या दिनांक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान

05/11/20	61	3634
22	34	166
2817	**03/11/20**	25
90	**22**	63
24	2666	**01/11/20**
91	128	**22**
04/11/20	40	1842
22	54	88
2437	**02/11/20**	09
63	**22**	27

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) का संचालन किया है। एक्यूईडब्ल्यूएस द्वारा पीएम2.5 के प्रदूषण स्तर में पराली की आग के योगदान का अनुमान लगाया गया है। 1 नवंबर को योगदान 9.7 प्रतिशत, 2 नवंबर को 7.4 प्रतिशत, 3 नवंबर को 32 प्रतिशत और 4 नवंबर को 17.8 प्रतिशत अनुमानित है।

दिल्ली सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को आर्थिक मदद

संजय बाटला

क्या सही में दिल्ली में रहकर भवन निर्माण में कार्य करने वाले श्रमिक को ही मिलेगी या किसी और को, बड़ा सवाल ?

दिल्ली सरकार अपनी दरियादिली दिखाने और फ्री बाटने वाली दुनियां की पहली सरकार है।

कहा से पैसा आता है और किसको जाता हैं यह तो खातों की जांच से ही पता चल सकता है पर जिनको नही जाता उनका पता लगाना बिना खाते की जांच किए भी लग जाता हैं और जिन्हें नही मिलती दिल्ली सरकार द्वारा घोषित आर्थिक मदद राशि अधिकतर वह व्यक्ति उसी कार्य के श्रमिक और दिल्ली में कार्यरत होते हैं जिनके लिए घोषित दिखाई और सुनाई जाती हैं यह आर्थिक मदद दिल्ली सरकार द्वारा।

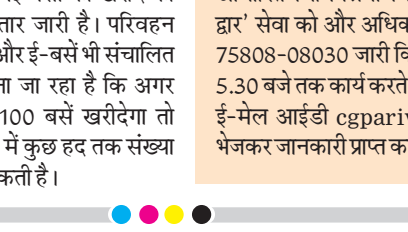

दिल्ली से अधिकतर श्रमिक कोरोना काल में पलायन कर गए थे इस बात की जानकारी आम जनता को भी है पर दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक मदद की लिस्ट देखी जाए तो पता चलता है कि दिल्ली से श्रमिको ने पलायन नही किया उल्टा बाहर के राज्यों के श्रमिक भी दिल्ली आ गए थे अपने जीवन की सुरक्षा और आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए।

आपकी जानकारी में जरूर होगा की उपराज्यपाल दिल्ली को श्रमिक संगठनों द्वारा इस मदद के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायते दर्ज कराई थी, उन शिकायतों की जांच में क्या निकल कर आएगा यह तो जांच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा पर क्या ?

ऐसे में नवम्बर 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक मदद सही श्रमिक और वह भी उस श्रमिक को जो दिल्ली में ही उपलब्ध है को दी जाएगी या मिलेगी इसकी क्या संभावनाएं बनती हैं ? क्योंकि इसके लिए तो कोई निर्देश जारी नही किए गए की आर्थिक मदद उसी श्रमिक को देनी है जो दिल्ली में इतने दिनो से रह कर काम कर रहे हैं और दिल्ली में उपलब्ध है।

2023-24 में निगम की 12 बसें कंडम होंगी और 835 बसें बचेंगी। 2024-25 में 55 बसें कंडम होने के बाद 780 रह जाएंगी।

देहरादून: परिवहन निगम ने नई बसें न खरीदीं तो पांच साल में 300 रह जाएंगी, फिलहाल 942 बसों का है रोडवेज का बेड़ा

एनटीवी संवाददाता

देहरादून । 2025-26 में सीधे 480 बसें कंडम होंगी, जिसके बाद निगम के पास केवल 300 बसें रह जाएंगी। इस लिहाज से परिवहन निगम के लिए नई रोडवेज बसों की खरीद बेहद अहम है। निगम के महाप्रबंधक कहा कहना है कि नई बसों की खरीद की प्रक्रिया भी लगातार जारी है।

उत्तराखंड परिवहन निगम ने बसें न खरीदीं तो अगले पांच साल में निगम के पास केवल 300 बसें रह जाएंगी। हालांकि निगम ने बड़े स्तर पर बसें खरीदने की योजना बनाई है। दरअसल, परिवहन निगम के पास फिलहाल 942 बसें हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस साल निगम की 95 बसें कंडम होने वाली हैं, जिसके बाद 847 बसें रह जाएंगी। 2023-24 में निगम की 12 बसें कंडम होंगी और 835 बसें बचेंगी। 2024-25 में 55 बसें कंडम होने के बाद 780 रह जाएंगी। 2025-26 में सीधे 480 बसें कंडम होंगी, जिसके बाद निगम के पास केवल 300 बसें रह जाएंगी। इस लिहाज से परिवहन निगम के लिए नई रोडवेज बसों की खरीद बेहद अहम है।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने बताया कि अनुबंधित बसों के लिए दोबारा टेंडर किया गया था, जिसमें करीब 150 लोग शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार, नई बसों की खरीद की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। परिवहन निगम सीएनजी और ई-बसें भी संचालित कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर निगम सालाना 100 बसें खरीदेगा तो अगले पांच साल में कुछ हद तक संख्या नियंत्रण में आ सकती है।

राज्योत्सव: 1293 युवाओं को मिला ऑनस्पाट लर्निंग लाइसेंस, परिवहन विभाग के स्टॉल में मिली सुविधा से लोग उत्साहित

रायपुर: राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव के दौरान परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में ऑनस्पाट सुविधा का लाभ उठाकर लोग काफी उत्साहित हुए। यहां 01 से 06 नवंबर तक छः दिन में 1 हजार 293 युवाओं को ऑनस्पाट लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। इनमें एक नवंबर को 103, दो नवंबर को 178, तीन नवंबर को 219, चार नवम्बर को 189, पांच नवम्बर को 279 और छः नवम्बर को 325 प्रदत्त लाइसेंस शामिल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को विभाग द्वारा दिनों-दिन आसान बनाया जा रहा है। इस तारतम्य में परिवहन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सुविधा ''तुहंर सरकार तुहंर द्वार'' का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक लोगों को घर बैठे ही लगभग 14 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। 'तुंहर सरकार, तुंहर द्वार' सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है। आवेदक चाही गई जानकारी ई-मेल आईडी cgparivahandispatch@gmail.com पर भी अपनी मेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.
-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.
-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.

वर्कप्लेस पर तरक्की के लिए महिलाओं को इन चुनौतियों का करना पड़ता है सामना

वर्कप्लेस पर महिलाओं को अपना करियर ग्राफ बेहतर बनाने के लिए कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है. ये मुश्किलें उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण के साथ साथ कई अन्य चुनौतियां भी पैदा कर देती हैं.

21वीं सदी में महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकीं हैं. फिर वह फाइनेंस सेक्टर हो, फोर्स हो या कोई अन्य क्षेत्र, पुरुषों के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और मिशन को पूरा करने के लिए सफलता भी हासिल कर रही हैं. लेकिन इसका मतलब ये कतई नही है कि हर महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से बाधाओं से परे हैं और उनका पुरुषों के समान ही बराबर का अवसर भी हासिल हो रहा है. यहां हम आपको बताते हैं कि वर्क प्लेस पर महिलाओं को अपने करियर ग्राफ बेहतर बनाने के लिए किन चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है जो उनके लिए कई बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं और हालात करियर से हाथ धोने तक की आ जाती है.

महिलाओं के लिए वर्कप्लेस की चुनौतियां

प्रेग्नेंसी

वूमन आइकॉन नेटवर्क के मुताबिक, ऑफिस में वैसे तो प्रेग्नेंट महिला के साथ भेदभाव करना कानूनी रूप से अपराध है. इसके अलावा अगर महिला प्रेगनेंसी में काम करना चाहती है और उसे जबरदस्ती लीव पर जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो इसे क्या कहा जाए. दरअसल, हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव की जरूरत महसूस नहीं होती और वे अपने करियर को बीच में छोड़कर पेड लीव पर नहीं जाना चाहती. दरअसल, ऐसा करने से उनके करियर को नुकसान हो सकता है.

समान वेतन

औसतन जगहों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काम अधिक करना पड़ता है लेकिन उनकी सैलरी पुरुषों की तुलना में कम होती है. वैसे तो महिला कर्मचारी कंपनी में पे ऑडिट की मांग कर सकती हैं लेकिन उसे मैनेजमेंट से टक्कर लेना पड़ सकता है जिससे उसकी नौकरी को खतरा हो सकता है. ऐसे में उन कंपनियों को ढूंडना चुनौतिपूर्ण है जहां समान वेतन की बात की जाती हो.

लीडरशिप के लिए मौका कम होना

कई ऐसे फर्म हैं जहां लीडरशिप पोजीशन के लिए महिलाओं और पुरुषों में अंतर देखा जाता है. ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों को हाई-प्रोफाइल, मिशन-क्रिटिकल असाइनमेंट के लिए आवंटित किया जाता है जो पेशेवर और मील स्टोन के रूप में काम करते हैं. ये संस्थान के पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकता है.

बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ये हैं 7 ज़रूरी बातें आगे देखें...

यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अभी भी एक समस्या है. अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो इसकी जानकारी मैनेजमेंट को देनी चाहिए और मैनेजमेंट को इसकी जांच करनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए. लेकिन कई जगहों पर मैनेजमेंट या बड़े लीडरशिप पोजीशन के लोग इन बातों को दबा देते हैं और महिला को नौकरी तक से हाथ धोना पड़ जाता है.

कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये ऐप्स

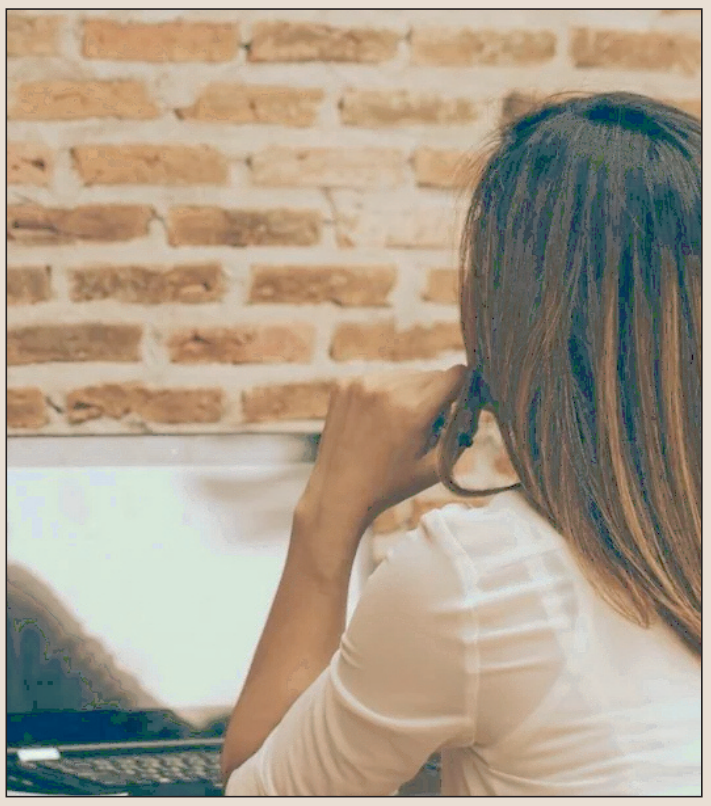

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है.

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज़ में ऐप्स की मदद से आगे बढ़ रही हैं और पैसे भी कमा पा रही हैं. सबसे खास बात यह है कुछ प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.

अगर आप किसी कारणवश अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई हैं, या आपने केवल 10वीं या 12वीं तक की ही पढ़ाई की है और आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, इस अब आपको ऐसा मौका मिल सकता है. क्योंकि देश में कई ऐसे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जो खासरकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. इन ऐप्स के इस्तेमाल से महिलाओं ने 2021 में तरक्की के कई रास्ते खोले और अब 2022 में भी ये उनकी मदद कर रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर (**Delhi-NCR**), मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज़ में बहुचर्चित 'अपना (**apna**)' ऐप ने महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाई है. बीते साल करीब लाखों महिलाओं ने इसका इस्तेमाल कर नौकरी पाई. सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.

इन ऐप्स पर सिर्फ अपनी जानकारी डालने के बाद उनके पास जरूरत के हिसाब से नौकरी पाने के ऑफर आते रहते हैं. 12वीं पास महिलाओं ने सबसे ज्यादा टेलीकॉलर, बीपीओ, बैक ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस, टीचर, अकाउंटेंट, एडमिन ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए आवेदन किया है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत प्लेटफॉर्म

इसी तरह खास महिलाओं के लिए चलाई जा रही सोशल नेटवर्किंग साइट 'शीरोज (**Sheroes**)' भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई है. यहां हर उम्र वर्ग की महिलाएं, ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जुड़ती हैं. वह नौकरी के अवसर भी तलाशती है, साथ ही अगर वह अपने लेवल पर किसी तरह का बिजनेस कर रही हैं, तो उसे प्रमोट भी करती हैं. बिजनेस वुमेन इसके सहारे अपना नेटवर्क मजबूत कर रही हैं. इस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई.

बिज़ी लाइफ में इन तरीकों से महिलाएं निकालें खुद के लिए समय

महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है. महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है.

कामकाजी महिलाओं (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में कुछ तरीकों की मदद से वे अपना काम आसान कर सकती हैं और अपने लिए समय बचा सकती हैं ताकि वे अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें.

आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टास्क हो गया है. इस समस्या से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं और जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए तो खुद के लिए समय निकालना नामुमकिन है. वर्किंग विमेन (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. जिसे पूरा करते-करते वे ना तो चैन की सांस ले पाती हैं और ना ही अपनी नींद पूरी कर पाती हैं. ऐसे में स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ता है.

इस समस्या को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

चाबियों पर लगाएं अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश

अक्सर जब किसी काम को जल्दी पूरा करना हो या हम जब जल्दी में होते हैं तभी छोटी-छोटी चीजों की वजह से देर होने लगती. ऐसे में आप अपने घर की कई चाबियों को अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश से रंग सकते हैं. इससे आपको पर्टिकुलर लॉक के लिए सारी चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं.

कंघी करते समय रखें ध्यान

ऑफिस जाते समय जल्दी-जल्दी में बालों को सुलझाने में महिलाएं बालों के साथ खींचतान करने लगते हैं. जिससे बाल अधिक टूटते हैं और नीचे गिर कर काम बढ़ा देते हैं. इससे बचने के लिए अपने हेयर ब्रश में बटर पेपर लगाकर कंघी करें. इससे बाल जल्दी सुलझ जाएंगे और नीचे भी नहीं गिरेंगे.

हेयर स्ट्रेटनर से प्रेस करें

सुबह के समय जल्दी रहे तो आप प्रेस के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके कपड़े जल्दी प्लेस होंगे और आपका समय बच जाएगा.

जो महिलाएं मां नहीं बन पातीं, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा: नई रिसर्च

महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है. (सांकेतिक तस्वीर)
महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है.

ब्रिटेन में हुई रिसर्च से पता चला है कि जिन औरतों में बांझपन (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका 16 फीसदी तक ज्यादा होती है. महिला को गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ में परेशानी हो तो बाद के सालों में दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है.

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी

लंदनः एक नए शोध से पता चला है कि महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने (infertility) की समस्या का संबंध दिल की बीमारी से भी होता है. ब्रिटेन में हुई रिसर्च के बाद दावा किया गया है कि जिन औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका बाकी महिलाओं से 16 फीसदी तक ज्यादा होती है.

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल में छपे इस शोध में कहा गया है कि महिलाओं के प्रजनन इतिहास से काफी हद तक पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है. महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

इस शोध के दौरान दो तरह के हृदयाघात यानी हार्ट फेल होने की स्टडी की गई. पहला preserved ejection fraction के साथ हार्ट अटैक (HFpEF) जिसमें दिल की मांसपेशियां खून पंप करने के बाद पूरी तरह फैल नहीं पातीं. दूसरा हार्ट फेल्योर विद reduced ejection fraction (HFrEF). इसमें बाएं वेंट्रीकल यानी दिल के निचले भाग के कोष से हर धड़कन के बाद जितना खून शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता. महिलाओं में हार्ट फेल के ज्यादातर मामले HFpEF के ही होते हैं.

शोध करने वाली टीम की लीडर और मैसाचूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ ने बताया कि रिसर्च के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि महिलाओं में थायरायड या जल्दी मेनॉपॉज़ जैसी समस्याओं का भी क्या प्रजनन क्षमता और दिल की बीमारी से कोई लेना-देना होता है या नहीं. लेकिन इस धारणा को लेकर किसी तरह के पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक ये तो पता था कि जिन महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की समस्या होती है, उनमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं. लेकिन बांझपन का दिल की बीमारी पर असर को लेकर कोई पुख्ता स्टडी नहीं हुई थी. आमतौर पर दिल की बीमारी को 50 साल के बाद की समस्या माना जाता है, जबकि बांझपन उम्र के 20वें, 30वें या 40वें पड़ाव पर आने वाली दिक्कत है. इसलिए इन दोनों के संबंध पर गौर नहीं किया जाता. अब महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की क्षमता का कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य का ध्यान तो रखा ही जा सकता है ताकि उन्हें दिल की बीमारियों से बचाया जा सके.

इनसाइड

दिल्ली में 9 नवंबर से खुल जाएंगे स्कूल: पर्यावरण मंत्री

नई दिल्ली । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 9 नवंबर से एक बार फिर स्कूल शुरू किए जाने की घोषणा की है। साथ ही पूरी क्षमता के साथ सरकारी ऑफिस चलेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को अब ऑफिस जाना होगा। फेज 4 का सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया है। हालांकि अभी भी फेज 3 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। बीएस3 पेट्रोल जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उन पर फेज 3 के तहत प्रतिबंध रहेगा, फेज 3 के तहत सभी प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर प्रदूषण में तेजी के साथ सुधार देखा जा रहा है। दिल्ली में लगे ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगी रोक भी हटा दी गई है।

इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए सभी ऑफिसों को पूरी क्षमता से कार्य करने को कह दिया गया है। वहीं, दिल्ली में हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है, लेकिन निजी निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी अभी जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतिम चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने पर केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल के नए निर्देशों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश को रद्द कर करने का निर्णय लिया गया है।

गाजीपुर लैंडफिल साइट का बड़ा हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के गाजीपुर कूड़े का पहाड़ एक बार फिर ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गाजीपुर बकरा मंडी के कारोबारियों ने बताया कि रविवार रात कूड़े के पहाड़ का बकरा मंडी के सामने का हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से गाजीपुर लैंडफिल साइट की दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। गाजीपुर बकरा मंडी में काम करने वाले वर्करों ने बताया कि गनीमत रही कि यह हादसा रात के वक्त हुआ। दिन के वक्त घटनास्थल के आसपास बकरा मंडी लगती है, जिसकी वजह से वहां काफी भीड़ होती है।

दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इरशाद कुरैशी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। रविवार होने की वजह से जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और हादसा दोबारा न हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वहीं घटना के संबंध पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के डीसी वंदना राव से पूछने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि एक सितंबर 2017 को भी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जमा कूड़े का पहाड़ ढह गया था। कूड़े का बड़ा हिस्सा हिंडन कैनाल रोड पर गिर गया था। इस हादसे में सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां मलवे की चपेट में आ गई थी।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, लेकिन राजधानी में इन वाहनों पर अभी भी जारी रहेगा बैन

सोमवार को दिल्ली में हवा चार से 12 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (**GRAP**) के तीसरे चरण के तहत लगाया गए थे, जिसे (ग्रेप का चौथा चरण) अभी तक नहीं हटाया गया है। साथ ही निजी विध्वंस और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 354 रहा।

एनटीवी संवाददाता

सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 354 रहा। रविवार को यह 339 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 15 अंकों की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 160 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और पीएम 10 का स्तर 275 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा।

नई दिल्ली। दिल्ली- एनसीआर की हवा सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। अलबत्ता, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 300 से भी नीचे यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पराली जलाने की घटनाओं और इसके धुएं की हिस्सेदारी में सोमवार को भी कमी देखने को मिली। सफर इंडिया का कहना है कि अभी अगले दो तीन दिन प्रदूषण की यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। हालांकि प्रदूषण से राहत तो मिली है लेकिन दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल वाहनों और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।

निजी विध्वंस और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध जारी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगाया गए थे, जिसे (ग्रेप का चौथा चरण) अभी तक नहीं हटाया गया है। साथ ही निजी विध्वंस और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 354 रहा। रविवार को यह 339 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 15 अंकों की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 160 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और पीएम 10 का स्तर 275 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा।

मंगलवार सुबह भी स्मॉग का असर दिखा।

ठंड के सीजन में दिल्ली-एनसीआर में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, स्मॉग के आगे पस्त सूरज की किरणें

आइएआरआइ के अनुसार 2532 घटनाएं दर्ज

दिल्ली के वायु प्रदूषण में सोमवार को पराली के धुएं की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत रही। हालांकि पराली जलाने की घटनाओं में विरोधाभास भी बना रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की 2532 घटनाएं रिकार्ड की गई जबकि सफर इंडिया के मुताबिक इन घटनाओं की संख्या 616 रही।

चार से 12 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली हवा

सोमवार को दिल्ली में हवा चार से 12 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। इसी के चलते प्रदूषण से लोगों को राहत मिल रही है। रविवार को भी उत्तर-पश्चिम की जगह पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी दिशा से हवा चली, जिसके चलते पराली का प्रदूषण भी दिल्ली तक अपेक्षाकृत कम पहुंचा।

इन शहरों में यह रही हवा की गुणवत्ता

शहर	एक्यूआइ
दिल्ली	354
फरीदाबाद	338
नोएडा	328
गुरुग्राम	305
गाजियाबाद	304
ग्रेटर नोएडा	298

नोट-मालूम हो कि 400 से नीचे एयर इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी जबकि 300 से नीचे खराब श्रेणी में रखा जाता है।

आम आदमी पार्टी का एमसीडी चुनाव में केंद्रीय मुद्दा कूड़ा होगा, भाजपा दिशाहीन पार्टी : आप

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद लोगों में खुशी है कि आखिरकार भाजपा को दिल्लीवालों ने चुनाव कराने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली में पिछले एक साल की भाजपा की गतिविधियों का अवलोकन करें, तो साफ-साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर भाजपा एक दिशाहीन पार्टी है। एमसीडी को लेकर भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलीला मैदान में आए, लेकिन 15 साल एमसीडी में सरकार चलाने के बावजूद उनके पास 15 साल की एक भी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं थी। एमसीडी के मई में चुनाव थे लेकिन जवाब देने की स्थिति न होने के चलते इन्होंने चुनाव टालने का सोचा, वरना जमानत जब्त होगी। पहले इस दिशाहीन पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र किए कि अगर चुनाव टालेगे तो हमारे अनुकुल परिस्थितियां बनेगी और चुनाव जीतेंगे।

उन्होंने कहा कि चुनाव टालने के बाद इन्होंने फिर सर्वे कराया और सर्वे में फिर भाजपा हार गई। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए जिसपर हम चुनाव लड़ सकें। ऐसे में दिल्ली में शराब नीति को लेकर झूठ पर झूठ बोलते रहे। इसके बाद फिर सर्वे कराया, जिसमें फिर भाजपा हार गई। इन्होंने सोचा कि अब क्या करें। अब सुनने में आ रहा है कि देश का सबसे बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर भाजपा का स्टार प्रचारक होगा।

उसके लेटर के दम पर दिल्ली एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। ईडी, सीबीआई और सारे झूठे आरोप जब तथ्यहीन हो गए, तब भाजपा को लग रहा है कि अब हमारी नैया दिल्ली में सुकेश चंद्रशेखर के लेटर के दम पर पार होगी। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें। अब चुनाव में नारा आया है कि सेवा ही विचार है, नहीं खोखले प्रचार है।

राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एमसीडी चुनाव में केंद्रीय मुद्दा कूड़ा होगा। उसके लिए दिल्ली में आठ नवंबर से कूड़े के ऊपर प्रत्येक बूथ पर जनसंवाद शुरू किया जाएगा। पार्टी के प्रतिनिधियों की तरफ से 20 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस जनसंवाद के लिए 600 प्रवक्ताओं की सूची तैयार की गई है। जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह वह लोग हैं जो कि चुनाव लड़ने के दावेदार नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जनसंवाद का आयोजन किया गया था, जिसका सकारात्मक असर पड़ा था। इसके जरिए लोगों के सुझाव लिए जाएंगे और कूड़े की समस्या के निस्तारण पर चर्चा की जाएगी।

वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में 13,682 पोलिंग बूथ हैं। आम आदमी पार्टी आठ नवंबर, यानी कल से 20 नवंबर तक हर एक बूथ पर जनसंवाद करेगी। उस जनसभा के दौरान हम दिल्ली की जनता से पांच प्रश्न पूछेंगे।

पाठक ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर हम दिल्ली की जनता के साथ संवाद करेंगे। अब कोशिश यह है कि कल शाम से हर एक वार्ड में 4 से ज्यादा बूथ संवाद किए जाएं जो कि हर दिन लगभग 1000-1200 बूथ संवाद होंगे। आठ नवंबर को शुरू होकर 20 नवंबर को यह बूथ संवाद पूरा हो जाएगा। इस दौरान हम दिल्ली की हर गली मोहल्ले में जाएंगे। जिसमें हम 13,682 से ज्यादा सभाएं दिल्ली में करेंगे।

भाजपा ने केजरीवाल को कहा वसूली कंपनी का सीईओ

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को सुकेश चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया तीसरा पत्र सामने आने के बाद इस मामले में और विवाद बढ़ गया है। सोमवार सुबह दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूरे मामले का हवाला देते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने की भी मांग की।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एकेवीसी यानी अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे जेल के अंदर के वसूली एजेंट से वसूली का काम करवा रहे हैं और इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं।

गुप्ता ने कहा कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर के तीसरे पत्र से खुलासा हुआ कि उसने सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को उनके फार्म हाउस पर पैसे दिए और तो और यह भी सामने आया कि तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी को किस तरह से मॉडल टाउन में अलग-अलग जगहों पर 12.5 करोड़ रुपए दिए गए।

उन्होंने आगे कहा कि पत्र में बताया गया है कि सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि सुकेश चंद्रशेखर पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियों को साक्ष्य देने के लिए भी तैयार है। प्रेस वार्ता में अपनी बात रखते हुए गुप्ता ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा, मामले की सीबीआई जांच की मांग करती है। इसके साथ ही यह भी मांग भी करती है कि आरोपित सत्येंद्र जैन को तुरंत प्रभाव से हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, ताकि वे जांच को प्रभावित न कर सकें। उन्होंने बताया कि पूरे मामले पर दिल्ली भाजपा इस बारे में एलजी से भी मुलाकात करेगी।

डीएमआरसी ने बीईएल साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

यह नवाचार को बढ़ावा देगा, स्थानीय कौशल को बढ़ाएगा, मेट्रो की तैनाती लागत को कम करेगा

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने आज एक स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (आई-सीबीटीसी) के विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। डीएमआरसी इस स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को बीईएल और सी-डैक के साथ विकसित कर रहा है।

डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा कि यह भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित सिग्नलिंग सिस्टम के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है और मेट्रो सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह नवाचार को बढ़ावा देगा, स्थानीय कौशल को बढ़ाएगा, मेट्रो की तैनाती लागत को कम करेगा और देश के भीतर ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग सिस्टम के क्षेत्र में विशेषज्ञता का विकास करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि ओम हरि पांडे (निदेशक, विद्युत) डीएमआरसी और मनोज जैन, निदेशक (आर एंड डी) बीईएल ने आज मेट्रो भवन में डीएमआरसी और बीईएल दोनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग तकनीक यानी सीबीटीसी को दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। डीएमआरसी और बीईएल ने संयुक्त रूप से आई-एटीएस (स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली) भी विकसित किया है जो वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है।

67 हजार करोड़ का निवेश लाखों लोगों को देगा रोजगार, ये हैं यमुना

यमुना प्राधिकरण ने 67 हजार करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। प्राधिकरण ने भूखंड योजना निकालकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। नवंबर में प्राधिकरण कुछ और योजनाएं निकालने जा रहा है।

नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने 67 हजार करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। प्राधिकरण ने भूखंड योजना निकालकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। नवंबर में प्राधिकरण कुछ और योजनाएं निकालने जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क में बड़े निवेश के लिए प्राधिकरण देश के कुछ शहरों में रोड शो करने जा रहा है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का निर्माण शुरू होने के बाद यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। निवेश प्रस्तावों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निवेश लक्ष्य को सात हजार करोड़ से बढ़ाकर 67 हजार करोड़ कर दिया है।

प्राधिकरण ने इसका रोडमैप भी तैयार कर लिया है। जिन योजनाओं के जरिये प्राधिकरण यह लक्ष्य पूरा करेगा, उन्हें चिह्नित कर उन पर अमल भी शुरू कर दिया है।

साल के आखिरी दो महीनों में राजस्व जुटाने की तैयारी

नवंबर और दिसंबर इस लिहाज से अहम होंगे। प्राधिकरण इन दो माह में भूखंड योजनाओं के जरिये खासा राजस्व जुटाने की तैयारी में है। प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाओं को चिह्नित कर लिया गया है। नई योजनाओं पर भी काम हो रहा है।

मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए होंगे रोड शो

यमुना प्राधिकरण ने हाल में दिल्ली में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए इन्वेस्टर समिट किया था। प्राधिकरण मुंबई, बेंगलुरू, अहमदाबाद समेत अन्य शहरों में रोड शो करने की तैयारी में है। साथ ही इजरायल, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में भी रोड शो होंगे।

फिल्म सिटी के लिए प्री बिड मीटिंग आज

यमुना प्राधिकरण फिल्म सिटी के विकासकर्ता के चयन के लिए सोमवार को लखनऊ में प्री बिड मीटिंग करेगा। औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव व करीब 20 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो फिल्म सिटी की वैश्विक निविदा को लेकर अपने सुझाव व जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे।

मेडिकल डिवाइस पार्क
3800

डाटा सेंटर
17000

फिल्म सिटी
10000

इलेक्ट्रिक क्लास्टर
8000

औद्योगिक क्लास्टर
7000

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब उड़ने लगेंगे विमान? वरिष्ठ आइएएस अफसर

एनटीवी न्यूज

एयरपोर्ट का विकास कार्य समय से पूरा करने के साथ भूअर्जन में आ रही बाधा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं। एयरपोर्ट को सड़क रेल कनेक्टिविटी की परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है।

नोएडा। गौतमबुद्धनगर के जेवर इलाके में देश के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। सितंबर 2024 में एयरपोर्ट से यात्री सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट के साथ ही जेवर को एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहालिंग (एमआरओ) का भी बड़ा केंद्र बनाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रदेश सरकार के इस सपने को साकार करने में जुटे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के सीईओ डा.अरुणवीर सिंह। एयरपोर्ट के निर्माण एवं उससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में धर्मेंद्र चंदेल व अरविंद मिश्रा ने डा.अरुणवीर सिंह से बात की। प्रस्तुत है इसके अंश...।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरे चरण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पांच अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें योगदान के लिए उत्तर प्रदेश को एक अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहां बनने वाले एमआरओ इसके लिए ट्रिगर प्वाइंट होगा। निवेश के साथ रोजगार का बड़ा केंद्र यहां होगा। नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तय समय से आगे चल रहा है। दूसरे चरण में एमआरओ व एक रनवे का निर्माण होना है। इसके लिए 1365 हेक्टेयर भूमि ली जा रही है। बड़ी परियोजनाएं ही देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाएंगी।

भूमि अधिग्रहण में किसानों की नाराजगी भी सामने आ रही है। आखिर कहां कमी है, जो किसान नाराज हैं?

नोएडा एयरपोर्ट के लिए किसानों ने आगे बढ़कर भूमि अधिग्रहण पर सहमति दी थी। दूसरे चरण के लिए भी 80 प्रतिशत किसानों की सहमति मिल चुकी है। जल्द ही धारा 11 का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। प्रतिकर व पुनर्वास को लेकर किसानों की कुछ असंतुष्टि थी। मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक में प्रतिकर में वृद्धि का फैसला हो चुका है। पहले चरण में विस्थापित किसानों के पुनर्वास स्थल पर कुछ कार्य जैसे कब्रिस्तान, श्मशान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण अभी नहीं हो सका है। संबंधित विभागों को यह काम करना है। इसके दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सीईओ सभी किसानों की समस्याओं को सुनने व उन्हें हल करने के लिए संकल्पित हैं। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है।

एयरपोर्ट के तीसरे व चौथे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण कब होगा?

-देखिये, यह सब एयरपोर्ट को मिलने वाले ट्रैफिक पर निर्भर करेगा। पहले चरण में दो रनवे के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवा की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में एक रनवे व एमआरओ के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। नोएडा एयरपोर्ट का विस्तार छह रनवे तक प्रस्तावित है। दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट की 80 से 90 मिलियन यात्री क्षमता है। 110 मिलियन के बाद यह पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा, इसलिए एनसीआर में दूसरे बड़े एयरपोर्ट की जरूरत थी। दुनिया के कई देशों अमेरिका, ब्रिटेन, इटली आदि में एक ही शहर में दो-दो एयरपोर्ट हैं। प्रदेश सरकार इस परियोजना में अति सक्रियता से कार्य कर रही है। एयरपोर्ट के लिए करीब छह हजार हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। तीसरे व चौथे चरण के लिए भूमि की उपलब्धता में कोई अड़चन नहीं है।

दूसरे चरण का काम कब तक शुरू होगा?

विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ हुए अनुबंध के अनुसार पहले चरण का निर्माण कार्य 1095 दिन यानि सितंबर 2024 तक पूरा होना है। इसकी नियमित निगरानी हो रही है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर को नियुक्त किया गया है। हर दिर चुनौती है और हर दिन का लक्ष्य है। अगले साल नवंबर में रनवे व दिसंबर तक टर्मिनल बिल्डिंग में लाइटिंग आदि का काम पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के चार से छह माह में रिक्वेस्ट फार प्रपोजल जारी कर दिया जाएगा।

एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट होने से आइजीआइ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इस पर क्या काम हो रहा है?

नोएडा एयरपोर्ट प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का श्रेष्ठ उदाहरण होगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, खुर्जा पलवल एक्सप्रेस-वे से जुड़ने के साथ हाईस्पीड ट्रेन, रैपिड ट्रेन, मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए बल्लभगढ़ से एयरपोर्ट तक 31 किमी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण एनएचएआइ कर रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे व यमुना एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। इससे गुरुग्राम व फरीदाबाद से भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक मेट्रो की डीपीआर तैयार हो रही है। इस रूट पर छह स्टेशन होंगे। बुलंदशहर के चोला रेलवे स्टेशन से भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की योजना है।

फेज दो में यमुना प्राधिकरण का विस्तार कब से होगा?

यमुना प्राधिकरण फेज दो की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। दोनों ही नोएडा एयरपोर्ट के लिहाज से काफी अहम है। एयरपोर्ट के नजदीक टप्पल क्षेत्र में लाजिस्टिक हब बनेगा। इसकी डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। इसमें निवेश के साथ रोजगार सृजन होगा। मथुरा में वृंदावन के नजदीक हेरिटेज सिटी बसाने की योजना है। इसकी डीपीआर जल्द ही प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। निवेश के साथ पर्यटन के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाकर बांके बिहारी मंदिर को सीधे यमुना एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।

इनसाइड

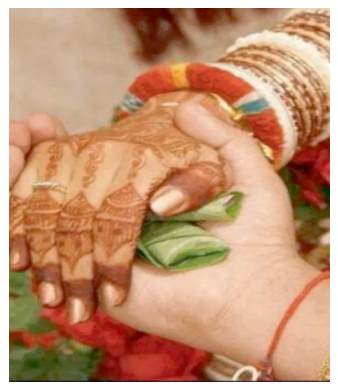

24 नवंबर को 2200 जोड़े लेंगे सात फेरे, योगी आदित्यनाथ देंगे आर्शीवाद

कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कलक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने बताया कि विवाह कार्यक्रम का आयोजन श्रम विभाग द्वारा कमला नेहरू नगर स्थित कमला नेहरू पार्क में किया जाएगा।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को गाजियाबाद आ सकते हैं। यहां पर उस दिन 2,200 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह के बंधन में बंधने वाले इन जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कलक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने बताया कि विवाह कार्यक्रम का आयोजन श्रम विभाग द्वारा कमला नेहरू नगर स्थित कमला नेहरू पार्क में किया जाएगा।

2200 जोड़े बधेंगे शादी के बंधन में

जिसमें गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर के 2,200 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही पात्र होंगे। इनका पंजीकरण कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए। अब तक गाजियाबाद से 250, बुलंदशहर से 250, हापुड़ से 300 श्रमिकों ने अब तक आवेदन किया है। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 75 हजार रुपये दिए जाएंगे, इनमें से 10 हजार रुपये पोशाक खरीदने के लिए और 65 हजार रुपये विवाह के बाद बैंकखाते में भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम में 25 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है।

निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लगी तो परिवर्तन संभव

2,200 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम 24 नवंबर को होना प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं, आवेदन करने वाले घरों में भी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं लेकिन नवंबर-दिसंबर में ही निकाय चुनाव भी होने प्रस्तावित हैं। उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बताया कि यदि 24 नवंबर से पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई तो कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए मोहद्दीनपुर ढबारसी में वैकल्पिक कार्यक्रम स्थल भी चिह्नित किया गया है। जिससे कि कार्यक्रम उसी दिन संपन्न कराया जा सके। प्रयास यह रहेगा कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर कमला नेहरू नगर में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 2,200 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य है। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल लड़के की उम्र 21 साल होनी आवश्यक है। सभी विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य विकास अधिकारी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ब्याज के साथ बिल्डरों से वसूलेगा 55 हजार करोड़, सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

धन की कमी से जूझ रहे नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों पर दोनों प्राधिकरणों के बकाया 55 हजार करोड़ रुपये वसूलने का रास्ता साफ कर दिया।

नोएडा। धन की कमी से जूझ रहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों पर दोनों प्राधिकरणों के बकाया 55 हजार करोड़ रुपये वसूलने का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने करीब एक वर्ष पहले मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसला सुनाया गया।

इसके साथ रिव्यू पिटिशन में प्राधिकरणों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत बिंदुओं को सही ठहराया गया। इससे उन 225 बिल्डरों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भारी भरकम रकम को दबा बैठे थे।

बता दें कि 25 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के मार्जिनल कास्ट आफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट (एमसीएलआर) के हिसाब से नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बिल्डरों से बकाया वसूल करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कोर्ट में 26 अक्टूबर को रिव्यू पिटिशन डाली थी।

प्राधिकरणों की ओर से इस याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (पूर्व सालिसिटर जनरल), मुकुल रोहतगी (पूर्व अटार्नी जनरल), वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र कुमार ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक साल पहले 13 नवंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर बिल्डरों को तगड़ा झटका दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की रिव्यू याचिका के सभी बिंदुओं को सही ठहरा अपने ही आदेश को पलट दिया है। इससे नोएडा में 90 डिफाल्टर बिल्डरों पर 40 हजार करोड़ और ग्रेटर नोएडा में 135 डिफाल्टर बिल्डरों से 15 हजार करोड़ रुपये की वसूली होगी। हालांकि नोएडा प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों से बकाया वसूली में एसबीआइ की एमसीएलआर की दर को नौ जून 2020 से वसूल किया जाएगा। इससे पहले लीज डीड शर्त में शामिल 11.5 प्रतिशत ब्याज, एक प्रतिशत प्रशासनिक ब्याज दर और तीन प्रतिशत पेनाल्टी ब्याज दर के हिसाब से बकाया वसूलने का नियम है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब दोनों प्राधिकरणों को 19 हजार 301 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन यूनिटेक व अन्य परियोजनाओं की देयताओं को अलग-अलग कर दें तो भी नोएडा प्राधिकरण को 5,860 करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 3838 करोड़ रुपये व दोनों प्राधिकरण का मिलाकर 9698 करोड़ वित्तीय हित सुरक्षित हो गए हैं।

वर्ष 2006 में नोएडा भू आवंटन नीति के तहत ग्रुप हाउसिंग में कुल लैंड की लागत का 10 प्रतिशत जमा कर भूखंड का आवंटन कर दिया जाता था। बाकी बकाया रकम किस्तों में जमा करनी होती थी। यह राशि छह-छह माह की किस्त पर आठ वर्ष में बिल्डरों को जमा करनी थी, जोकि जमा नहीं की गई। इससे बिल्डरों पर नोएडा प्राधिकरण में 26 हजार करोड़ बकाया हो गया, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 15 हजार करोड़ रुपये बकाया हो गया।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जमकर मनमानी की। ग्रुप हाउसिंग के लिए दिया गया एमसीएलआर का आदेश स्वतः ही संस्थागत व वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए लागू कर दिया। इससे नोएडा में 15 हजार करोड़ रुपये का प्राधिकरण का भुगतान रोक दिया। इस आदेश के बाद बिल्डरों ने नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग विभाग का 26 हजार करोड़ का भुगतान रोक दिया था।

वाणिज्यिक, संस्थागत विभाग का करीब 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों का भुगतान रोक दिया था। इससे नोएडा प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग का 26 हजार करोड़ रुपये के बकाया के साथ-साथ 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बकाया बिल्डरों का हो गया। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में करीब 50 हजार ऐसे फ्लैट खरीदार हैं, जिनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल सका है। सौ प्रतिशत बिल्डरों को भुगतान करने के बावजूद अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। इसमें नोएडा में 30 हजार खरीदार और ग्रेटर नोएडा में 17 हजार से अधिक फ्लैट खरीदार शामिल हैं। इनका मालिकाना हक तभी संभव है, जब बिल्डर बकाया रकम प्राधिकरण में जमा करे। ऐसे में खरीदारों की समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है।

याचिका में यह तथ्य किए गए शामिल

-राष्ट्रीकृत बैंकों की ब्याज प्रणाली
-प्राधिकरण की वित्तीय क्षति
-प्राधिकरण के वित्त न होने से पेंडिंग विकास कार्य

शहर बकाया	बिल्डर	प्रोजेक्ट	डिफाल्टर
नोएडा हजार करोड़	65	116	90	40
ग्रेटर नोएडा हजार करोड़	100	275	135	15

मरीजों में डेंगू के लक्षण, जांच रिपोर्ट आ रही नेगेटिव; 13 नए मरीज मिले

इमरजेंसी की बात करें तो हर दिन 10 से 12 बुखार के मरीजों में डेंगू के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इनमें तीन से चार मरीज ही डेंगू के मिल रहे हैं जबकि अन्य मरीजों में लक्षण तो डेंगू के हैं लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ रही है।

नोएडा। जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई ऐसे मरीज भी मिल रहे हैं, जिनमें डेंगू के लक्षण तो दिख रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। बीते दिन 13 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों का अलग-अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई सेंटिनल लैब में इनकी जांच की गई है। अब तक 138 मरीजों की पुष्टि हुई है।

मरीजों में डेंगू रिपोर्ट मिल रही नेगेटिव

जिला अस्पताल की ब्लड बैंक प्रभारी डा. बिंदु का कहना है कि बुखार के ऐसे मरीज आ रहे हैं, जिनके प्लेटलेट्स काउंट कम आ हैं, जबकि संक्रमण बताने वाले मार्कर टीएलसी के भी नीचे है। ऐसे मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इनकी डेंगू रिपोर्ट निगेटिव मिल रही है। इन्हें नान डेंगू वायरल सिंड्रोम बताकर इलाज कर रहे हैं। अन्य मरीजों में मलेरिया, वायरल बुखार के लक्षण मिल रहे हैं। इमरजेंसी की बात करें तो हर दिन 10 से 12 बुखार के मरीजों में डेंगू के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इनमें तीन से चार मरीज ही डेंगू के मिल रहे हैं, जबकि अन्य मरीजों में लक्षण तो डेंगू के हैं, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। यही हाल सेक्टर-24 स्थित ईएसआइसी अस्पताल व सेक्टर-30 चाइल्ड पीजीआइ का है। जहां ऐसे सैकड़ों मरीज भर्ती हैं।

कागजों में हुआ छिड़काव, फैल गए मरीज

शासन ने अभियान के तहत डेंगू प्रभावित इलाकों में छिड़काव के निर्देश दिए हैं, लेकिन विभाग ने कागजों में छिड़काव कर वाहवाही लूट रखी है। शहर में डेंगू तेजी से फैल गया। मलेरिया विभाग का कहना है कि अभियान चलाकर छिड़काव करने के साथ घरों और आसपास जमे पानी, टायर और गमलों को साफ करवाया जा रहा है। डेंगू से निपटने को विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

डेंगू के बेड बढ़ाकर 14 किए गए

जिला अस्पताल में डेंगू के बेडों की संख्या को बढ़ाकर दस से 14 कर दिया गया है। वर्तमान में दो बेड पर डेंगू पाजीटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। सीएमएस डा. पवन कुमार अरुण का कहना है कि भर्ती मरीजों की हालत स्थिर है। वार्ड में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी दवाएं रखवा दी गई हैं।

इस वर्ष विभिन्न बीमारियों के मिले मरीजों की संख्याः

बीमारी	कुल रोगी
डेंगू	138
मलेरिया	92
चिकनगुनिया	3
स्क्रब टाइफस	11

जेवर स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रस्तावित फोटो।

Noida News: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब उड़ने लगेंगे विमान? वरिष्ठ आइएएस अफसर डा.अरुणवीर सिंह ने खोला राज

यह भी पढ़ें

इनसाइड

टॉप 10 कारों की लिस्ट में शामिल हैं मारुति की ये 7 कारें

मारुति ने हाल ही में ऑल्टो के10 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यह वजह भी है कि मारुति ऑल्टो इस समय देश की नंबर वन कार बन गई है।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी को भारतीय बाजार में काफी प्यार मिलता है। यही वजह है कि पिछले महीने देश में बिकने वाली टॉप 10 कारों की सूची में मारुति की 7 गाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। आइये जानते हैं उन 7 कारों की सेल्स रिपोर्ट के बारे में।

मारुति सुजुकी ऑल्टो

अक्टूबर में कंपनी ने मारुति ऑल्टो की 21,260 यूनिट्स बेचीं। अक्टूबर 2021 में बेची गई 17,389 इकाइयों की तुलना में कार की बिक्री में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऑल्टो K10 लॉन्च होने की वजह से इस गाड़ी की बिक्री में भारी इजाफा देखने को मिला है।

मारुति सुजुकी वैगन आर

कंपनी ने पिछले महीने मारुति सुजुकी वैगन आर की 17,945 यूनिट्स की बिक्री की। यह पिछले साल की इसी महीने की 12,335 इकाइयों से 45% अधिक है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

अक्टूबर महीने में मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 17,231 यूनिट्स की बिक्री हुई। 88% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए कार पिछले महीने भारत में तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली कार के रूप में उभरी।

मारुति सुजुकी बलेनो

ऑटो कंपनी ने अक्टूबर 2022 में मारुति सुजुकी बलेनो की 17,149 इकाइयां बेचीं। प्रीमियम हैचबैक को हाल ही में एक CNG संस्करण मिला है, जो पिछले साल बेची गई 15,573 इकाइयों की तुलना में इसकी 10 फीसद की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

मारुति सुजुकी डिजायर

मारुति सुजुकी डिजायर ने अक्टूबर 2022 में 12,321 इकाइयों की बिक्री के साथ 53 फीसद की वृद्धि दर्ज की। पिछले साल इसी महीने के दौरान यह आंकड़ा 8,077 था।

मारुति सुजुकी अर्टिगा

मारुति सुजुकी एर्टिगा की 10,494 इकाइयां अक्टूबर 2022 में बेची गईं। हालांकि, एमयूवी ने पिछले साल 12,923 इकाइयों की बिक्री में गिरावट देखी गई है।

महंगी हो गई Skoda Kushaq और Slavia कारें

नई दिल्ली। वाहन निर्माता कंपनी स्कोडा ने अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके कुशाक और स्लाविया मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। अब इन दोनों के लिए आपको 60,000 रुपये तक अतिरिक्त देने होंगे। तो चलिए इनकी नई कीमतों के बारे में जानते हैं।

कीमतों में हुई कितनी बढ़ोतरी

आपको बता दें कि इस साल यह स्लाविया की यह दूसरी बढ़ोतरी है। स्लाविया की कीमतों को विभिन्न वेरिएंट के हिसाब से 1,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। वहीं, कुशाक 20,000 रुपये से 60,000 रुपये तक महंगी हो गई है।

इस हिसाब से स्कोडा कुशाक की शुरुआती कीमत 11.59 लाख रुपये हो गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 19.69 लाख रुपये होगी। दूसरी तरफ, स्कोडा स्लाविया के लिए ग्राहकों को अब 11. 29 लाख रुपये चुकाने होंगे, जो कि टॉप मॉडल के लिए 18.40 लाख रुपये है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम की है।

स्कोडा कुशाक का इंजन

स्कोडा कुशाक के इंजन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 114bhp की पावर और 178nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं, ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 6-स्पीड मैन्युअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

अगले साल तक हो सकता यामहा इलेक्ट्रिक स्कूटर का दीदार

Yamaha Electric Scooter का काम जोरों से है। इसे भारत में अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यह एक बेहतर रेंज वाला ई-स्कूटर होगा जिसमें 70 किलोमीटर तक की रेंज देने की क्षमता होगी। साथ ही इसे नियो नाम दिया जा सकता है।

नई दिल्ली। बाइक निर्माता कंपनी यामाहा जल्द ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखने वाली है। यह 2023 तक अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश कर सकती है, जिसे Ola, Hero, TVS और एथर इलेक्ट्रिक स्कूटरों के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, पहले मिली जानकारी के मुताबिक, इसे देश में नियो (Neo) नाम से लॉन्च किया जा सकता है।

यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक

लुक के मामले में आगामी यामाहा स्कूटर एक मैक्सी स्कूटर होगा, जिसमें एलईडी सेटअप वाले हेडलैंप और टेललैंप, चौड़े एलॉय व्हील्स, 27-लीटर अंडरसीट स्टोरेज और कंफर्टेबल सीट सहित कई खूबियां देखने को मिल सकती है।

यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंजन पावर

यामाहा के इंजन पावर में इसके ग्लोबल मॉडल की तरह ही 50.4 वॉल्ट और 19.2 वॉल्ट के दो बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। यह 2.5 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़े होंगे। साथ ही इसे सिंगल चार्ज पर 70 किलोमीटर तक की रेंज देने के लिए डिजाइन किया गया है।

यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स

अपकमिंग Yamaha Electric Scooter में कई नए फीचर्स को देखे जाने की उम्मीद है। इसमें LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्मार्ट की इंटीग्रेशन, एबीएस, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और एक रियर मोनोशॉक, डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स को जोड़ा जा सकता है। राइडर सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे के पहियों में ड्रम ब्रेक मिलता है।

यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत

अनुमान है कि यामाहा इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में 2.50 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, हाल ही में इसे यूरोपीय बाजार में इसे 3,099 यूरो (करीब 2.58 लाख रुपये) की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था।

रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 करने जा रही है अपना डेब्यू, इंजन से लेकर हेडलाइट तक मिलेगा बहुत कुछ नया

Royal Enfield Super Meteor 650 एक क्रूजर बाइक है जिसमें 648cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है। वहीं इसका डेब्यू कल इटली में होने वाले 2022 EICMA शो में किया जा सकता है। भारत में भी इसके लॉन्च होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। बाइक निर्माता रॉयल एनफील्ड अपनी नई बाइक सुपर मीटियोर बाइक को पेश करने कर लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे कल यानी कि 8 नवंबर को इटली में होने वाले 2022 EICMA शो में पेश किया जाएगा। बता दें कि मीटियोर 650 को हाल के दिनों में भारत में टेस्ट करते देखा गया था, इससे अनुमान है कि रॉयल एनफील्ड ग्लोबल मार्केट के बाद जल्द ही इसे भारत में भी लॉन्च कर सकती है।

Royal Enfield Super Meteor का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो अपकमिंग सुपर मीटियोर 650 को एक क्रूजर बाइक के रूप में लाया जा रहा है। इसमें गोलाकार आकार के एलईडी हेडलैंप और फर्स्ट-फॉर-आरई अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, सिग्नेचर एलईडी टेलटैंप, मस्कुलर फ्यूल टैंक, ट्विन एग्जॉस्ट पाइप और रियर एंड पर आगे की ओर फेस किए इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे।

Super Meteor 650 का इंजन

इंजन के रूप में नई मीटियोर में 648cc का ट्विन-सिलेंडर फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिए जाने की बात कही जा रही है। यह इंजन 47PS की पावर और 52Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। ट्रांसमिशन के लिए एक स्लीपर और असिस्ट क्लच के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा जा सकता है।

Super Meteor 650 के फीचर्स

रॉयल एनफील्ड के बाकी मॉडल्स की तरह ही इस अपकमिंग बाइक में भी कई लेटेस्ट फीचर्स को रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सेमी-डिजिटल, सिंगल-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ओडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर हो सकते हैं। सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम के साथ देखा जा सकता है। वहीं, सुरक्षित राइडिंग के लिए बाइक में ट्विन-साइड रीयर शॉक, फ्रंट और रीयर डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS सिस्टम और ब्लैक एलॉय व्हील्स को रखा जा सकता है।

जीप ग्रांड चिरोकी जल्द होगी आपकी, कंपनी ने शुरू की प्री-बुकिंग

2022 Jeep Grand Cherokee इसी महीने दस्तक दे सकती है। यह एक जबरदस्त इंजन पावर वाली एसयूवी होगी जिसमें 2.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। भारत में इसका मुकाबला BMW X5 Volvo XC90 और मर्सिडीज-बेंज GLE से होगा।

नई दिल्ली। ऑफ रोड एसयूवी के लिए फेमस जीप अपनी नई ग्रैंड चिरोकी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है और इसके लिए ग्राहकों को 50,000 रुपये की टोकन मनी देनी होगी।चेरोकी की प्री-बुकिंग चुनिंदा जीप डीलरशिप और ऑनलाइन पोर्टल पर की जा रही है।

कंपनी ने इसकी लोकल असेंबली भी शुरू कर दी गई है। इसे महाराष्ट्र स्थित जीप के रंजनगांव फैसिलिटी प्लांट में बनाया जा रहा है और इसे 11 नवंबर को लॉन्च किए जाने की बात कही जा रही है।

जबरदस्त पावरट्रेन के साथ आ सकती है चेरोकी

जानकारी के मुताबिक, जीप में 2.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। विदेशों में मिलने वाले इसके मॉडल के आधार पर उम्मीद है कि इसमें 3.6-लीटर पेंटास्टार V6 पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 290hp की पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं, ट्रांसमिशन के लिए एसयूवी में आठ-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को जोड़े जा सकता है।

कई शानदार फीचर्स से हो सकती है लैस

जीप ग्रैंड चेरोकी के फीचर्स की बात करें तो करें तो इसमें स्लीक एलईडी हेडलैम्प्स और 7-स्लैट ग्रिल को शामिल किया जा सकता है। वहीं, इसके केबिन में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चेरोकी में हवादार और पावर्ड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग पैड और इलेक्ट्रिक टेलगेट को भी रखा जा सकता है।

Jeep Grand Cherokee की कीमतों की बात करें तो इसे 90 से 95 लाख रुपये की रेंज में लाया जा सकता है। वहीं, लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला BMW X5, रेंज रोवर Velar, Volvo XC90 और मर्सिडीज-बेंज GLE से होगा।

(जयंती/ 8 नवंबर विशेष)

समतामूलक समाज के उन्नायक गुरुनानक देव

डॉ. अशोक कुमार भार्गव

पिता नानक जी को सच्चा सौदा करने के लिए कम कीमत पर वस्तुएं खरीद कर अधिक कीमत पर बेचने के लिए कहते हैं किंतु नानक पिता के दिए पैसों से भूखे प्यासे साधु-संतों को रसद खरीद कर दे देते हैं। उनकी दृष्टि में भूखे को अन्न देना ही सच्चा सौदा है। सुल्तानपुर लोदी में नौकरी करते हुए वह घर जोड़ने की माया से विमुख सारी तनख्वाह गरीबों और जरूरतमंदों को बांट देते हैं। उनके मन में नकार बिल्कुल नहीं है।

सिख धर्म के संस्थापक आदि गुरु नानकदेव जी मानवीय कल्याण के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विसंगतियों, विडंबनाओं, विषमताओं, आडंबरों,कर्मकांडों अंधविश्वासों तथा जातीय अहंकार के विरुद्ध लोक चेतना जागृत की। साथ ही तत्कालीन लोदी और मुगल शासकों के बलपूर्वक मतांतरण तथा बर्बर अत्याचारों के विरुद्ध प्रखर राष्ट्र वाद का निर्भीकतापूर्वक क्रांतिकारी शंखनाद किया। उन्होंने विभिन्न उपमाओं, रूपकों, प्रतीकों और संज्ञाओं से परिपूर्ण अमृतवाणी से एक ओंकार सतनाम, आध्यात्मिक पवित्रता ,सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सद्भाव, कौमी एकत, बंधुता लैंगिक समानता ,नारी सम्मान के साथ ही भेदभाव रहित समतामूलक समाज की स्थापना का मार्गप्रशस्त कर अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को संगठित संघर्ष प्रदान किया।

गुरुनानक देव जी का जन्म 1469 में लाहौर के पास तलवंडी नामक स्थान में जो अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, हुआ था। इनके पिता पटवारी कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। वह बचपन से ही ईश्वरीय प्रतिभा से संपन्न दिव्यात्मा थे जो ध्यान, भजन, चिंतन, सत्य, अहिंसा, संयम और आध्यात्मिक विषयों में ही अधिक रुचि लेते थे। उनके जीवन की अनेक अलौकिक, असाधारण और चमत्कारिक घटनाएं हैं जो उनकी कर्म, भक्ति और ज्ञान साधना की महानता तथा अनासक्त भाव को प्रकाशित करती हैं। पाठशाला में वे शब्द के साधक बन अपने समय से बहुत आगे भविष्य को पढ़ रहे थे। परा विद्या से अक्षरों की वर्णमाला में उन्हें परमात्मा की एकता और उनके स्वरूप का रहस्य दिखाई देता था। उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई को देख उनके गुरु और मुल्ला गुरु भी शिष्य बन गए। यज्ञोपवीत संस्कार के समय वे कहते हैं की 'जनेऊ के लिए दया का कपास हो, उस दया रूपी कपास से संतोष रूपी सूत काता गया हो, साधना की गांठ हो। जैसे कर्मयोगी कृष्ण ने गीता में उद्घाटित किया कि आत्मा को आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, पवन उड़ा नहीं सकता उसी प्रकार जनेऊ ऐसा हो जो न कभी टूटे न कभी मैला हो और न कभी नष्ट हो। जिसने इस रहस्य को समझ लिया वही इस संसार में धन्य है। चरवाहे का कार्य करते समय वृक्ष के नीचे सो जाते हैं तब वृक्ष की छाया सूर्य से निरपेक्ष हो जाती है। नानक जी का मन बच्चों के साथ खेलने कूदने में नहीं लगता साधु-संतों की संगति अच्छी लगती है। पिता कालू मेहता नानक के स्वास्थ्य की चिंता से वैद्य को बुलाते हैं। नानक जी वैद्य से कहते हैं कि मेरे शरीर में कोई विकार नहीं है। मेरा दर्द उस परमात्मा से न मिल पाने यानी वियोग से पैदा हुआ दर्द है। यदि इसकी कोई औषधि तुम्हारे पास हो तो ले आओ।

पिता नानक जी को सच्चा सौदा करने के लिए कम कीमत पर वस्तुएं खरीद कर अधिक कीमत पर बेचने के लिए कहते हैं किंतु नानक पिता के दिए पैसों से भूखे प्यासे साधु-संतों को रसद खरीद कर दे देते हैं। उनकी दृष्टि में भूखे को अन्न देना ही सच्चा सौदा है। सुल्तानपुर लोदी में नौकरी करते हुए वह घर जोड़ने की माया से विमुख सारी तनख्वाह गरीबों और जरूरतमंदों को बांट देते हैं। उनके मन में नकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए वे विवाह के लिए हां करते हैं क्योंकि इसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व से पलायन न करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सच्चा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। वे साधु होकर भी जन समाज में ही रहे उनके सुख-दुख में भाग लेकर उन सा ही जीवन व्यतीत करते रहे। मोदी खाने में एक दिन आटा तोलते समय तेरा-तेरा अर्थात ईश्वर का करते हुए सारा आटा ही तोल दिया। नानक जी नदी में स्नान करने जाते हैं तो 3 दिन बाद एकाएक प्रकट होकर कहते हैं कि न कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। मैं इंसान और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं मानता। ईश्वर मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों से करता है न कि उसके हिंदू या मुसलमान होने के कारण।

एक काजी ने नानक को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए आदेश दिया। नानक मस्जिद में गए जरूर लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। शासक दौलत खान ने नमाज न पढ़ने के लिए नानक से पूछा तो नानक ने कहा कि मैं नमाज किसके साथ पढ़ता। आप भी तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे आपका तो ध्यान तो कंधार में घोड़े खरीदने में था। वही काजी इस चिंता में डूबे हुए थे कि कहीं घोड़ी का नवजात शिशु आंगन के कुएं में न गिर जाए। पांच वक्त की नमाज के बारे में पूछने पर नानक जी कहते हैं कि उसकी पहली नमाज सच्चाई है, ईमानदारी की कमाई दूसरी नमाज है, खुदा की बंदगी तीसरी नमाज है, मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना उसकी पांचवीं नमाज है। जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है।

नानक की दृष्टि में किसी भी प्रकार की सामर्थ्य शक्ति या क्षमता प्राप्त करके एकांत में जा बैठना और उसका उपयोग समाज हित के लिए न करना कर्तव्य से विमुख होना है अपने दायित्वों से पलायन करना है। गुरु नानक जी ने लगभग 15 वर्षों तक भारत की चारों दिशाओं के प्रमुख स्थानों की यात्रा की। अंत में अफगानिस्तान, ईरान, इराक और अरब तक गए। इस दौरान उनकी अनुभूति की गहनता और अधिक प्रखर हुई। वे जीवन पर्यंत पांच प्रार्थनाओं सत्य, यथार्थ, ईश्वर के नाम पर दया, सद्विचार तथा ईश्वर की स्थिति और गुणगान के लिए समर्पित रहे। गुरुनानक जी कहते थे कि ऊंच-नीच और भेदभाव की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना होगा उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि हम सब मिल जुल कर रहें की शिकायत न करें और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें ईमानदारी से परिश्रम कर अपनी आजीविका कमाई मिल बांट कर खाएं और मर्यादा पूर्वक ईश्वर का नाम जपते हुए आत्म नियंत्रण रखें किसी भी तरह के लोग अथवा लालच को त्याग कर परिश्रम और न्याय उचित तरीके से कर्मठता पूर्वक धन कमाए।

उन्होंने सामाजिक सद्भाव और एकता के लिए एक ही धर्मशाला में एकत्रित होकर सामूहिक लंगर ,सामूहिक आराधना और सामुदायिक जीवन के आधार पर छुआछूत और अस्पृश्यता के विरुद्ध व्यापक चेतना जागृत की। वे लंगर में तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते थे जब तक भोजन बनाने वाले और आंगन में झाड़ू लगाने वाले उनके साथ पंगत में आकर नहीं बैठ जाते थे। दीन-दुखियों, पीड़ितों, निर्बलों, उपेक्षितों और ठुकराए हुए जनों के उद्धारक नानक ने अछूत लालू की मेहनत की कमाई की रोटी से दूध और मलिक भागो के पकवान से जो झूठ फरेब घूस और बेईमानी से बना था, खून टपका कर कहा कि वह व्यक्ति ऊंचा है जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसी में से कुछ गरीबों को दान करता है। उनका विश्वास है कि गुरु कृपा से ईश्वर को अपने अंतस में प्रतिष्ठित करें तभी ईश्वर दर्शन संभव है। यह संसार जो ईश्वर का ही मंदिर है जो गुरु के बिना अंधकारमय है। नानक की दृष्टि में सृष्टिकर्ता एक है परंतु उनके रूप अनेक हैं। वे आदि अनादि मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त है। स्वयं की कोई इच्छा न रखते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आचरण करना ही उस परम सत्ता को प्राप्त कर लेने का एकमात्र विकल्प है। सुख-दुख में फंसा हुआ इंसान संसार का संपूर्ण वैभव समर्पित करने के बाद भी कोई सुख या आनंद नहीं खरीद सकता क्योंकि सृष्टि के सभी पदार्थों का प्रकटीकरण ईश्वर की इच्छा का ही अस्तित्व है। वह सृष्टि का रचनाकार और संहारक भी हैं। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला भी है। ईश्वर की उदारता असीम, दया करुणा अप्रतिम और आज्ञा अनुपमेय है। उनकी अनुकंपा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे ईश्वरीय प्रतिभा से संपन्न दिव्यात्मा थे जिन्होंने मानव मात्र में ईश्वर का वास माना। उनकी कथनी करनी में अन्तर नहीं था। वह जो कहते थे उसे अपने आचरण में उतारते भी थे। वह सभी धर्मों व समाज के सभी लोगों को समान भाव से देखते थे। गुरुनानक देव जी ने सदैव इस बात पर बल दिया कि हम सब मिलजुल कर रहें। किसी का अहित न करें और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। ईमानदारी से परिश्रम कर अपनी आजीविका कमाएं। मिल-बांटकर खाए और मर्यादापूर्वक ईश्वर का नाम जपते हुए आत्मनियंत्रण रखें। किसी भी तरह के लोभ अथवा लालच को त्यागकर परिश्रम और न्यायोचित तरीके से कर्मठतापूर्वक धन कमायें। उन्होंने सही विश्वास, सही आराधना और सही आचरण की शिक्षा दी। हमारे प्रेरणापुंज गुरु नानक जी ने उस निराकार अनंत प्रभु की जय जयकार करते हुए यही प्रार्थना की कि वे भ्रमर की तरह प्रभु के चरण कमलों पर मधु की अभिलाषा से मंडराते रहे। वे प्रभु की महानता का वर्णन करने में असमर्थ है। उनकी दृष्टि में शब्द गुरु और आत्मा शिष्य है। यही जीवन का सौंदर्य है। शब्द के बिना अंधविश्वास और पाखंड नष्ट नहीं होता और न ही अहंकार से मुक्ति मिलती है।

जातीय अहंकार की दूषित मानसिकता के संकीर्ण गलियारों में भटकता हुआ भ्रमित समाज समतामूलक समाज के निर्माण का मार्गप्रशस्त नहीं कर सकता। कहने को तो यह देख संतों महात्माओं, धर्माचार्यो का देश है जहां पेड़, पौधों पशु, पक्षी और यहां तक की पत्थरों की भी पूजा की जाती है किंतु यह कैसा दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए दीन हीन अछूत व्यक्ति को छूने से पवित्रता भ्रष्ट हो जाती है। यह मिथ्या विश्वास किसी भी सभ्य समाज के प्रगतिशील होने का संकेत कैसे हो सकता है? निसंदेह 'कीरत करो, नाम जपो और वंड छको' तथा दसवंध का अमूल्य मंत्र एवं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हमारे जीवन के उच्च आदर्शों मूल्यों की प्रेरक धरोहर है। उन्होंने अंतिम समय में भाई लेहणा को कठिन परीक्षा के बाद बिना किसी भेदभाव, पूर्वाग्रह के योग्यता के आधार पर गुरु पद प्रदान कर एक स्वस्थ परंपरा का शुभारंभ किया। आज हम मंदिरों में उन मूर्तियों का ध्यान कर रहे हैं जिन्हें हमने ही बनाया है किंतु उनका ध्यान कब करेंगे जिसने हमें बनाया है।

संपादक की कलम से

सबसे प्रदूषित दिल्ली

दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यदि पुराने आंकड़ों के आधार पर आकलन करें, तो भी दिल्ली विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर था। अब स्थिति बदतर हो रही है। विश्व स्तर पर 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची तैयार की गई है। उनमें से 28 शहर भारत के हैं। राजधानी दिल्ली 'गैस चैंबर' तो पहले ही बन चुकी थी। न्यायाधीशों और चिकित्सकों ने ऐसी टिप्पणियां की हैं, लेकिन वायु प्रदूषण राष्ट्रीय समस्या बनता जा रहा है। दिल्ली में औसत आदमी खांस रहा है। आंखों में जलन है और नाक लगातार बह रही है। सांस घुट रही है या फूलने लगती है। फेफड़ों के कैंसर फैलने के आसार बढ़ रहे हैं। स्ट्रोक आम रोग हो गए हैं। दिल का दौरा पडना, डायबिटीज का बढना, अस्थमा, डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम, स्किन की समस्याएं, समझने की क्षमता पर चोट आदि रोग 'खतरनाक संकेत' दे रहे हैं। राजधानी के ही अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या 30-35 फीसदी बढ़ गई है। छोटे बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे, शेष घर से काम करेंगे। जिन पार्कों में सुबह टहलने और व्यायाम करने वालों की भीड़ होती थी, वे अब लगभग सूने पड़े हैं। दिल्ली महानगर की हवा गुणवत्ता का औसत स्तर अब भी 400 से अधिक है। यह 'बेहद खतरनाक' प्रदूषण का आंकड़ा है। वायु की सामान्य गुणवत्ता 100 के नीचे ही होती है, लेकिन बीते 15 दिनों से प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' अथवा 'बेहद खतरनाक' है। यह जानलेवा प्रहार हर साल अक्तूबर से शुरू होता है और जनवरी तक झेलना पड़ता है।

हालांकि पराली का जलाना तो 15 नवंबर तक कम हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण का यही कारक नहीं है। राजधानी के पड़ोसी शहरों-गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद आदि-में तो प्रदूषित हवा का स्तर 500 को भी छू चुका है। क्या हमारी सरकारें संवेदनहीन होकर खामोश बनी रहेंगी? क्या पराली जलाने से ही इतना भयानक प्रदूषण होता है? क्या चीन को उदाहरण मानकर और लंदन, मैक्सिको शहरों से सबक लेकर हम प्रदूषण को कम नहीं कर सकते? चीन ने अपने देश में करीब 40 फीसदी प्रदूषण कम किया है, नतीजतन वहां औसत उम्र 2 साल बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने मैक्सिको को पृथ्वी का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया था, लेकिन वह 1989 में कारों पर पाबंदी लगाने वाला 'प्रथम देश' बना। राजधानी दिल्ली में 50 फीसदी से ज्यादा प्रदूषण वाहनों के कारण है। पराली जलाने से औसतन 38 फीसदी प्रदूषण हो रहा है। इनके अलावा कूड़ा जलाना, आग, प्रदूषित उद्योग, चूल्हा जलाना, सडक़ की धूल, निर्माण-कार्य आदि भी प्रदूषण के बुनियादी कारक हैं। जब प्रदूषण 'बेहद खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया, तो दिल्ली में प्रदूषित वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी चस्पा की गई है। परिवहन और दुकानों के सम-विषम फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली में भी सीएनजी वाले वाहन ही चलाए जा सकेंगे। सौभाग्य समझा जाए कि दिल्ली मेट्रो रेल से लाखों यात्री इधर-उधर आते-जाते हैं। मेट्रो से कोई प्रदूषण नहीं होता। अलबत्ता दिल्ली परिवहन विभाग की और निजी बसों के 'ज़हर' को निगलने को हम विवश रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी (आप) की सरकारें हैं, लिहाजा 'केंद्र बनाम आप' की सियासत से प्रदूषण का एक भी कण कम नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय का बयान है कि पंजाब में किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 1347 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन मशीनें किसानों तक नहीं पहुंची अथवा किसान पराली जलाने के ही आदी हैं।

8 नवम्बर का इतिहास

देश-दुनिया के इतिहास में 08 नवंबर की तारीख तमाम वजह से खास है। इस तारीख का आजाद भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी से रिश्ता है। उन्हें इस तारीख को देश पुण्य तिथि पर नमन करता है। वो 08 नवंबर, 1960 को वह टोक्यो पहुंचे थे। वहां रेस्तरां में खाना खाते समय उनका निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को दिल्ली वापस लाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गाय। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू समेत प्रमुख भारतीयों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था।

एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी पहले रॉयल एयर फोर्स में शामिल हुए थे और बाद में भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारियों में शामिल हैं। 01 अप्रैल, 1954 को ही वह भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बनाए गए थे। उन्होंने भारतीय वायुसेना को दुनिया की ताकतवर वायुसेना बनाने में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करते हैं। सुब्रतो मुखर्जी बाद वाली श्रेणी में आते हैं। उनका जीवन ठोस इरादे, समर्पण और पूरी तरह से सेवा के हितों के लिए प्रतिबद्ध होने की मिसाल है। ब्रितानीराज में भारत के लोग काफी समय से रक्षा सेवाओं में उच्च पदों पर भारतीय के प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार इस आवाज की अनसुनी कर रही थी। लेकिन वर्ष 1930 आते-आते ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि ज्यादा समय तक वह भारतीयों की मांग को नहीं टाल सकती। इसके बाद धीरे-धीरे सेनाओं का 'भारतीयकरण' किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 08 अक्टूबर, 1932 को भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई।

सुब्रतो मुखर्जी का जन्म 05 मार्च, 1911 को पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख परिवार में हुआ। उनके पिता सतीश चंद्र मुखर्जी आईसीएस अफसर थे और मां चारुलता मुखर्जी प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी थीं। उनके दादा ब्रह्म समाज से जुड़े थे। उनके नाना प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। 1939 में उनकी शादी शारदा पंडित से हुई। वह प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थीं जो बाद में गुजरात और फिर तत्कालीन आंध्र प्रदेश की राज्यपाल बनीं। उनका एक बेटा है। अपने तीन भाई-बहन में सुब्रतो सबसे छोटे थे। उनका शुरुआती जीवन पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर और चिनसूरा में गुजरा। शुरू से ही वह वायुसेना में शामिल होने का सपना देखते थे। उनको वायुसेना में शामिल होने की प्रेरणा अपने चाचा इंद्र लाल रॉय से मिली थी। रॉय रॉयल फ्लाइंग कोर में तैनात थे।

सुब्रतो की शुरुआती शिक्षा कलकत्ता के डायोसेशन स्कूल और लॉरेटो कॉन्वेंट एवं यूके के हैम्पस्टीड में हुई। 1927 में उन्होंने बीरभूम जिले स्कूल से मैट्रिक पास किया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में दाखिला लिया और एक साल बाद यूके गए जहां कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। वर्ष 1929 में सुब्रतो मुखर्जी ने क्रेनवेल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और लंदन मैट्रिकुलेशन पास किया।

इजरायल में नेतन्याहू का पुनरोदय

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

इजरायल में इन दिनों जितनी फुर्ती से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, दुनिया के किसी अन्य लोकतंत्र में ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। बेंजामिन नेतन्याहू लगभग डेढ़ साल बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। उनका यह पुनरोदय असाधारण हैं। वे इजरायल के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो वहीं पैदा हुए हैं। उनसे पहले जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, वे बाहर के किन्हीं देशों से आए हुए थे। जब 1948 में इजरायल का जन्म हुआ था, तब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका आदि कई देशों के गोरे यहूदी लोग वहां आकर बस गए थे। उन्हीं में से एक का बेटा जो 1949 में जन्मा था, अब इजरायल का ऐसा प्रधानमंत्री है, जिससे ज्यादा लंबे काल तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा। 47 साल की उम्र में इजरायल के प्रधानमंत्री बनने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। वे कई बार हारे और जीते।

उन्हें दक्षिणपंथी माना जाता है। वे फौज के सिपाही होने के नाते 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में अपनी बहादुरी दिखा चुके थे। यह वह वक्त था, जब इजरायल ने डंडे के जोर पर सीरिया से गोलान की पहाड़ियां, जॉर्डन का पश्चिमी किनारा, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था। उस आक्रामक संस्कार से मंडित नेतन्याहू ने जब इजरायली राजनीति में प्रवेश किया तो वे अरब-विरोधियों के प्रवक्ता बन गए। नरमपंथी प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या के बाद 1996 में हुए चुनाव में इजरायल की जनता ने घनघोर अरब-विरोधी नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। नेतन्याहू उस 'ओस्लो एकॉर्ड' के विरोधी थे, जो इजरायल और फलिस्तीन के दो राज्यों को मान्यता दे रहा था। दो राज्यों का यह समाधान आतंकवाद की भेंट चढ़ गया और नेतन्याहू ने उस समझौते की धुर्रियां बिखेर दीं।

उन्होंने इजरायल द्वारा कब्जाए गए इलाकों को खाली करने से मना कर दिया, अरबों को इजरायल से निकाल बाहर करने की मुहिम चलाई और फलिस्तनियों से समझौते के सारे रास्ते बंद कर दिए। नेतन्याहू ने अमेरिका से नजदीकी बढ़ाई और ईरान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान छेड़ दिया। उन्होंने ओबामा-काल में ईरान के साथ हुए परमाणु-समझौते का विरोध किया और ईरान के विरुद्ध परमाणु शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की धमकी भी दी। उनके ईरान-विरोध ने अरब देशों के सुन्नी शासकों को इजरायल के नजदीक ला दिया। अब इजरायल के मिस्र, सउदी अरब, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान आदि राष्ट्रों से भी ठीक-ठाक संबंध बन गए हैं। भारत और रूस के साथ भी इजरायल के संबंध पहले से बेहतर बनाने में नेतन्याहू का विशेष योगदान है। उन्हीं के प्रयत्न के फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे और वे खुद दो बार भारत आ चुके हैं। भारत के साथ इजरायल के सामरिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध पहले से भी ज्यादा घनिष्ट होने की संभावना है लेकिन फलस्तीन का मामला अब ज्यादा उलझ सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार में यहूदी उग्रवाद के प्रवक्ता भी शामिल हैं।

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

टीम इंडिया का 'सूर्योदय'

सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय और भारतीय क्रिकेट के नए 'मास्टर ब्लास्टर' हैं। उनकी तुलना दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज रहे एबी डिबिलियर्स से की जाने लगी है, क्योंकि वह मैदान पर 360 डिग्री की बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं। यानी मैदान पर चारों तरफ शॉट्स खेलने में माहिर हो गए हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन क्षितिज पर उभरते वह ऐसे बल्लेबाज हैं, जो आज आईसीसी रैंकिंग में 'नंबर वन' हैं। इस साल सूर्यकुमार इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 1026 रन ठोंके हैं। वह टी-20 क्रिकेट में शतक भी जमा चुके हैं और अद्र्धशतकों की गिनती हर मुकाबले के साथ बढ़ रही है। युवराज और केएल राहुल के बाद, सबसे तेज अद्र्धशतक बनाने वाले, वह तीसरे बल्लेबाज हैं। आज सूर्यकुमार उस मुकाम पर हैं, जहां कभी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने लंबे वक्त तक अपना वर्चस्व कायम रखा था।

रोहित शर्मा भी उसी जमात के बल्लेबाज हैं, हालांकि आजकल वह लंबी, ठोस पारियां खेलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यदि 2016 के बाद आज टीम इंडिया विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची है, तो उसमें करीब 60 फीसदी भूमिका 'विराट-सूर्य' ने निभाई है। दोनों ने 471 रन बनाए हैं और टीम के कुल 9 में से 6 अद्र्धशतक भी ठोंके हैं। 'विराट-सूर्य' तीन-तीन अद्र्धशतक बना चुके हैं और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का ताज पहनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। भारत की पराजित होती पारी को, अंततः, जिताने में 'विराट-सूर्य' की ब्लास्ट पारियों का योगदान रहा है। तीन ओवर में 48 रन अथवा पांच ओवर में 79 रन कोई सामान्य बल्लेबाजी नहीं है। यह काम सिर्फ 'विराट-सूर्य' ने करके दिखाया है। 1983 में भारत को प्रथम विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव कहते रहे हैं-'पहले अंतिम चार में पहुंचने का सूर्योदय देखो। उसे जीतने की पुरजोर कोशिश करो। अपनी कमियों की खुद समीक्षा करो। उसके बाद आप चैम्पियन बनने की दहलीज पर खड़े हो।' टीम इंडिया आज उसी दौर में है। जिस टीम में हारते-हारते जीतने का माद्दा हो, वही चैम्पियन बनने के मुकाम तक पहुंचने में सक्षम होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की जीत ऐसी थी मानो पराजय के जबड़ों से उसे खींच लाए हों! लिहाजा टीम इंडिया मुग़ालते में नहीं है कि सेमीफाइनल में उसका मुकाबला विश्व की 'नंबर दो' टीम इंग्लैंड से है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि टीम इंडिया दुनिया की शेष क्रिकेट को पराजित कर 'नंबर वन' पर आसीन हुई है।

बेशक इंग्लैंड एक सशक्त टीम है और वे आक्रामक खेल के दीवाने हैं, लेकिन टीम इंडिया भी एक संतुलित और सफल टीम साबित होते हुए इस मुकाम तक पहुंची है। हमने इंग्लैंड के खिलाडियों के साथ आईपीएल में खूब खेला है, उनका खेल और क्रिकेट की शैली से हम बखूबी परिचित हैं और इंग्लैंड की टीम को उसी की ज़मीन पर कई बार पराजित भी किया है। कोई भी पक्ष अपराजेय नहीं है। टीम इंडिया की बड़ी चिंता यह है कि कप्तान रोहित शर्मा अपनी 'रिकॉर्डधारी मुद्रा' में नहीं हैं। उनके तेवर जल्द ही लौटें। अलबत्ता राहुल और विराट अपने रंग में लौट चुके हैं। चौथे नंबर की बल्लेबाजी की चिंता सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दी है। पेस गेंदबाजी सफल रही है। अर्शदीप की प्रतिभा 'सूर्योदय' जैसी ही है और वह अभी तक 10 विकेट ले चुके हैं। शमी की गेंदबाजी बेहद सटीक साबित हो रही है। आर. अश्विन भी उसी धार, सटीकता और कैरम गेंदबाजी करने में सफल साबित हों, जिसके लिए वह दुनिया में विख्यात हैं। कपिल देव मानते हैं कि बहुत छोटी-छोटी कमियां हैं, जिन्हें खेलते हुए भी दुरुस्त किया जा सकता है। संपूर्ण सफल संयोजन तो किसी भी टीम का नहीं हो सकता। यकीनन टीम इंडिया अब खिताब जीतने के मूड में आ गई है। सिर्फ दो कदम बाकी हैं। हमें एडिलेड की उस पिच पर सेमीफाइनल खेलना है, जो विराट की सबसे पसंदीदा पिच है। क्रिकेट प्रेमियों का जुनून देखने लायक है।

इजरायल में भारत के मित्र की वापसी

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

पाकिस्तान और चीन भारत के पड़ोसी हैं। इनकी फितरत जगजाहिर है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण और प्रशिक्षण मिलता है। चीन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का बचाव करता है। इस संदर्भ में नेताान्याहू ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत को खुला समर्थन दिया था।

इजरायल की भौगोलिक स्थिति संवेदनशील है। राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर नेतृत्व से उसकी परेशानी बढ़ती है। इस तथ्य को वहां के लोगों ने समझा है। इसके चलते राजनीतिक संक्रमण काल का समापन हुआ। बेंजामिन नेतान्याहू की एक बार फिर सत्ता में वापसी हुई। पहले भी वह प्रधानमंत्री के रूप में इजरायल को मजबूत नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के हिंसक मंसूबों को वह नाकाम करते रहे है। इजरायल की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाये रखने की उनमें दृढ़ इच्छाशक्ति रही है। फिर भी इसे इजरायल का आंतरिक मसला कहा जा सकता है। लेकिन नेतान्याहू का पुनः प्रधानमंत्री बनना भारत के भी हित में है। उन्होंने भारत की भौगोलिक स्थिति को समझा है। उसके अनुरूप विदेश नीति निर्धारित करने का साहस दिखाया है।

पाकिस्तान और चीन भारत के पड़ोसी हैं। इनकी फितरत जगजाहिर है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण और प्रशिक्षण मिलता है। चीन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का बचाव करता है। इस संदर्भ में नेतान्याहू ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत को खुला समर्थन दिया था। उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान के विरोध में भारत के प्रत्येक कदम का इजरायल समर्थन करेगा। इतना ही नहीं आतंकवाद से मुकाबले के लिए इजरायल सामरिक सहायता देने पर भी सहमत हुआ था। वस्तुतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से इजरायल के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। नेतन्याहू इजरायल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने लगातार बारह वर्षों तक और कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक देश पर शासन किया। उन्हें पिछले साल अल्पमत में आने के बाद सत्ता से हटना पड़ा था। बेंजामिन नेतान्याहू की लिकुड पार्टी के गठबन्धन को बहुमत मिल गया है। यायर लैपिड की येश अतीद पार्टी, रिलीजियस जियोनिज्म,नेशनल यूनिटी,शास और यूनाइटेड टोरा जुदाइस्म के गठबंधन को पराजय का सामना करना पड़। इजरायल में पिछले चार चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था।

वस्तुतः नरेन्द्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति में नया अध्याय जोड़ा था। इजरायल की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उस यात्रा के दौरान हुए सात समझौतों ने सात दशक की कसर पूरी कर दी थी। दूरियां नजदीकियां बन गईं। जल, थल और नभ तक सहयोग का विस्तार हो गया। यह सामान्य यात्रा नहीं थी। भारतीय राजनीति को देखते हुए इस संबंध में निर्णय करना आसान नहीं था। इसके लिए इच्छाशक्ति व साहस की जरूरत थी। मुसीबत में साथ देने वाले को सच्चा मित्र माना जाता है। निजी जीवन की ऐसी अनेक बातें विदेश सम्बन्धों पर लागू होती हैं। रिश्तों में गर्मजोशी न होने के बावजूद पाकिस्तान के हमलों के समय उसने हमेशा भारत का साथ दिया। प्रत्येक युद्ध में उसने सहायता दी। समर्थन किया। जबकि अरब देशों का समर्थन व सहानुभूति पाकिस्तान की तरफ होती थी। ऐसे में इजरायल के साथ संबंधों में बहुत पहले ही बड़ा सुधार करना चाहिए था। इस दौरान मिस्र जैसे कई अरब देशों ने भी इजरायल से सम्बन्ध बहाल किए थे। इजरायल तो भारत के साथ सच्ची दोस्ती का निर्वाह कर रहा था। मोदी ने राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन नहीं किया। उन्होंने राष्ट्र के हित को वरीयता दी। इसके चलते ही वह इजरायल जाने का निर्णय कर सके। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का स्थायी तत्व होता है। अन्य तत्वों का स्थान इसके बाद आता है। इसके पहले के नेतृत्व ने इजरायल से मित्रता का महत्व समझा था। पीवी नरसिंहा राव के समय 1992 में इजरायल से कूटनीतिक सम्बद्ध की शुरुआत जरूर की गई थी। 1950 में इजरायल को भारत द्वारा दी गई सीमित मान्यता का यह अगला चरण था। अटल बिहारी बाजपेयी ने इसे आगे बढ़ाया। उनके समय में इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत आये थे। कांग्रेस की सरकारें फलिस्तीन, अरब मुल्क और इजरायल से एक साथ अच्छे सम्बन्ध रखने पर विचार करने में विफल रहीं थीं। इजरायल का मध्यपूर्व में अस्तित्व एक हकीकत है। इसे अरब देश भी मान चुके हैं। फिलिस्तीन में भी निर्वाचित सरकार है। भारत के उनके साथ भी अच्छे सम्बन्ध हैं। मोदी ने इस नीति को मजबूत बनाया है। गाजा पट्टी, पश्चिमी तट और शरणार्थी समस्या का समाधान होना चाहिये। लेकिन यह कार्य इजरायल के अस्तित्व को नकार के नहीं हो सकता। हमास जैसे आतंकी संगठनों का दबाव नेतान्याहू को कभी मंजूर नहीं रहा। एक बार फिर मतदाताओं ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। आतंकवादी पत्थरबाजी हरकतों से निपटने की उनकी नीति बहुत स्पष्ट है। वह तौल के हिसाब बराबर करते है। यही इजरायल की स्थापित नीति रही है। 1967 के युद्ध में उसने गाजा व पश्चिमी तट के इलाकों पर कब्जा जमाया था। यासिर अराफात के नेतृत्व में लम्बा संघर्ष चला। लेकिन इजरायल ने सुरक्षा की गारंटी मिले बिना किसी हिस्से को खाली करने से इंकार कर दिया था। इजरायल की आतंकवाद विरोधी रणनीति विश्व में सर्वाधिक कारगर मानी जाती है। इसी के बल पर उसने अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाया है। यहूदी राष्ट्र मात्र सत्तर वर्ष पहले का नहीं है। इस जमीन पर उनका दावा ही सबसे पुराना है।

इनसाइड

बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कीमतें संशोधित करें निर्यातक : गोयल

नई दिल्ली। निर्यातक अल्पावधि की चुनौतियों से निपटने और बाजार हिस्सेदारी को बरकरार रखने के लिए कीमतों को अस्थायी रूप से संशोधित करें। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में शिरकत करते हुए यह बात कही। वाणिज्य एवं उद्योग ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि वाणिज्य मंत्री गोयल ने उद्योग जगत से अपने निर्यात बाजारों पर पकड़ बनाए रखने के लिए पहल करने को कहा है। गोयल ने निर्यातकों से कहा कि अल्पकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने कीमत ढांचे में अस्थायी बदलाव करते हुए अपना बाजार बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ पिछले कुछ महीनों में देश की निर्यात गतिविधियों में नरमी आने के बीच आयोजित बैठक में गोयल ने कई सुझाव दिए। उन्होंने निर्यातकों से कहा कि उन्हें वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों का उपयोग अपने लाभ के लिए करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही गोयल ने अरंडी जैसे अनूठे उत्पादों की निर्यात संभावनाएं टटोलने का आह्वान किया और मंत्रालय के अधिकारियों से इन उत्पादों के प्रोत्साहन में मदद देने को भी कहा है। उल्लेखनीय है कि देश का निर्यात सितंबर महीने में 4.82 फीसदी की वृद्धि के साथ 35.45 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 25.71 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।

जर्मन कंपनी मेट्रो कैश के भारतीय कारोबार को खरीदने की तैयार में अंबानी

नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की झोली में एक और कंपनी आने वाली है। रिलायंस रिटेल जर्मनी की रिटेल कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के भारतीय कारोबार को 50 करोड़ यूरो (4,060 करोड़ रुपये) में खरीद सकती है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि रिलायंस रिटेल और मेट्रो कैश एंड कैरी के बीच होने वाले इस डील में कंपनी के 31 होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जमीन और मालिकाना हक वाली अन्य संपत्तियां शामिल हैं। दरअसल रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और इस डील से उसे बी2बी श्रेणी में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की रिलायंस रिटेल और मेट्रो कैश एंड कैरी के बीच इस डील को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। पिछले हफ्ते जर्मन कंपनी मेट्रो रिलायंस रिटेल के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। हालांकि, दोनों कंपनियों ने फिलहाल इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि मेट्रो कैश एंड कैरी फिलहाल भारत में होलसेल ब्रांड के तहत 31 स्टोर का संचालन कर रही है। मेट्रो एजी ने साल 2003 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, लेकिन अब वह भारतीय बाजार से निकलने की तैयारी में है। मर्चेंट बैंकर जेपी मॉर्गन ऑर गोल्डमैन सैश ने मेट्रो कैश एंड कैरी कंपनी के कारोबार का वैल्यू करीब एक अरब डॉलर आंका था।

अब फेसबुक की मेटा कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी में

नई दिल्ली। ट्विटर के बाद दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा में 09 नवंबर से बड़े पैमाने पर छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंपनी दुनियाभर में करीब 12 हजार कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। मेटा में अभी 87,000 कर्मचारी हैं। इससे पहले ट्विटर इंक ने पिछले हफ्ते करीब 3700 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। इसके बाद कर्मचारियों की संख्या घटकर आधी रह गई है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क के बाद मेटा प्लेटफॉर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग भी बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रहे हैं। इस साल कंपनी के शेयरों में करीब 73 फीसदी की भारी गिरावट आई है। दरअसल फेसबुक यानी अब मेटा प्लेटफॉर्म्स को टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स से कड़ी टक्कर मिल रही है।

वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को दी राजस्व घाटा अनुदान की 8वीं किश्त

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की आठवीं मासिक किश्त जारी कर दी है। राज्यों को यह किश्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। दरअसल, 14 राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत (राजस्व घाटा अनुदान) जारी किया जाता है।

ये समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जानी है। मंत्रालय ने इसी क्रम में 14 राज्यों को यह आठवीं मासिक किश्त जारी की है। नवंबर महीने की आठवीं मासिक किश्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गई है।

आयोग की सिफारिश के मुताबिक पीडीआरडी अनुदान राशि हासिल करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी होना है।

उतार-चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 0.39 प्रतिशत और निफ्टी 0.47

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली। दिनभर उतार-चढ़ाव का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ कारोबार करके बंद हुआ। शेयर बाजार ने आज मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया था, लेकिन दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक गिरकर लाल निशान में पहुंच गए। आखिरी 2 घंटे में हुई खरीदारी के सपोर्ट से सेंसेक्स 0.39 प्रतिशत और निफ्टी 0.47 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए।

आज के कारोबार में बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। पीएसयू बैंक इंडेक्स आज साढ़े चार साल के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद होने में सफल रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स आज 428 अंक की मजबूती के साथ 41,687 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स में भी अच्छी खरीदारी होती नजर आई। दूसरी ओर कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयर दबाव में कारोबार करते नजर आए। पूरे दिन के कारोबार के बाद मिडकैप और स्मॉलकैप के शेयरों में ओवरऑल खरीदारी का रुख बना रहा।

पूरे दिन भर के कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1,999 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,173 शेयर मुनाफा कमाकर हरे निशान में और 826 शेयर नुकसान उठाकर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 18 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में और 12 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 33 शेयर हरे निशान में और 17 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के सेंसेक्स ने आज 237.77 अंक की मजबूती के साथ 61,188.13 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही सेंसेक्स तेज छलांग लगाकर 61,401.54 अंक तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद मुनाफावसूली के चक्कर में शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई, जिसके कारण सेंसेक्स लगातार नीचे गिरता चला गया। बीच-बीच में खरीदारों ने लिवाली करके शेयर बाजार को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन बिकवाली के दबाव की वजह से सेंसेक्स में गिरावट बनी रही।

लगातार हो रही बिकवाली के कारण सेंसेक्स दोपहर 1:30 बजे तक 236 अंक की कमजोरी के साथ आज के सबसे निचले स्तर 60,714.36 अंक तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद बाजार में खरीदारी का जोर शुरू हो गया, जिसकी वजह से सेंसेक्स ने निचले स्तर से रिकवरी करना शुरू कर दिया। आखिरी 2 घंटे के कारोबार में हुई खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक 234.79 अंक की मजबूती के साथ 61,185.15 अंक स्तर पर बंद होने में सफल रहा।

सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने भी आज मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। ये सूचकांक 94.60 अंक की बढ़त के साथ 18,211.75 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही निफ्टी ने जोरदार छलांग लगाई और 18,255.50 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद बाजार में शुरू हुई मुनाफावसूली के कारण ये सूचकांक भी लगातार गिरता चला गया। बीच-बीच में छिटपुट खरीदारी भी होती रही, लेकिन लगातार हो रही बिकवाली के कारण निफ्टी की गिरावट जारी रही।

बिकवाली के दबाव के कारण दिन के दूसरे कारोबारी सत्र में 1:30 बजे के करीब निफ्टी 52.40 अंक की कमजोरी के साथ आज के सबसे निचले स्तर 18,064.75 आज तक गिर गया। इसके बाद शुरू हुई खरीदारी ने इस सूचकांक को निचले स्तर से रिकवरी करने का मौका दिया। खरीदारी के इस सपोर्ट से निफ्टी ने 85.65 अंक की बढ़त के साथ 18,202.80 अंक के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। पूरे दिन हुई खरीद बिक्री के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 8.81 प्रतिशत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.40 प्रतिशत, अडाणी इंटरप्राइजेज 3.32 प्रतिशत, बीपीसीएल 2.79 प्रतिशत और आयशर मोटर्स 2.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ आज के टॉप 5 गेनर्स की सूची में शामिल हुए। दूसरी ओर डिवीज लेबोरेट्रीज 8.86 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 2.45 प्रतिशत, सिप्ला 1.33 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 1.26 प्रतिशत और अडाणी पोर्ट्स 1.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ आज के टॉप 5 लूजर्स की सूची में शामिल हुए।

होंडा कार्स इंडिया के उत्पादन का आंकड़ा भारत में 20 लाख इकाई के पार

नई दिल्ली। जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा कोर्स इंडिया का भारत में कुल उत्पादन का आंकड़ा 20 लाख इकाई के पार पहुंच गया है। कंपनी ने अपने 20 लाखवें वाहन का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र में किया है। कंपनी ने यह जानकारी दी।

होंडा कार्स इंडिया ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि भारत में कुल उत्पादन का आंकड़ा 20 लाख इकाई के पार हो गया है। कंपनी ने बताया कि उसके 20 लाखवें वाहन का उत्पादन राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र में हुआ है। होंडा मोटर लिमिटेड कंपनी ने भारत में उत्पादन की शुरुआत दिसंबर, 1997 में किया था। कंपनी ने परिचालन शुरू करने के बाद भारत में अबतक 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है।

होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ताकुया त्सुमुरा ने जारी बयान में कहा कि 20 लाख इकाइयों के उत्पादन का ये आंकड़ा पिछले 25 साल के दौरान होंडा की 'मेक इन इंडिया' के बारे में प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि कंपनी अपने सिटी और अमेज सेडान वाहनों को घरेलू बाजार में बेचने के अलावा 15 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनका निर्यात भी करती है।

उल्लेखनीय है कि होंडा फिलहाल सिटी और अमेज सेडान, डब्ल्यूआर-वी एसयूवी और जैज हैचबैक जैसी कारों का निर्माण करती है। कंपनी इन चार मॉडलों में से होंडा सिटी सेडान का हाइब्रिड वेरिएंट भी बेचती है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कंपनी की योजना अगले साल तक भारतीय बाजार में एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने है।

ईएसी-पीएम के अध्यक्ष देबरॉय ने सिंगल रेट जीएसटी का दिया सुझाव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन विवक देबरॉय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में बदलाव की मांग के बीच बड़ी बात कही है। देबरॉय ने जीएसटी प्रणाली में सिर्फ एक दर का सुझाव दिया है। देबरॉय ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में यह बात कही। देबरॉय ने कहा कि कराधान प्रणाली मुक्तता या छूट रहित होनी चाहिए। हालांकि, देबरॉय ने स्पष्ट किया है कि उनकी इस राय को ईएसी-पीएम का सुझाव नहीं माना जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों का कर संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 15 फीसदी है जबकि सार्वजनिक ढांचे पर सरकार के खर्च की मांग कहीं ज्यादा है। ईएसी-पीएम) के चेयरमैन विवक देबरॉय ने कहा कि जीएसटी पर यह मेरी राय है। उन्होंने कहा कि उत्पाद कोई भी हो जीएसटी दर एक होनी चाहिए। हालांकि, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कभी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके इस विचार को ईएसी-पीएम का सुझाव नहीं समझा जाए। देबरॉय ने कहा कि जीएसटी को लागू करने से पहले आर्थिक मामलों के विभाग ने 17 फीसदी जीएसटी राजस्व निरपेक्ष दर (आरएनआर) का अनुमान दिया था लेकिन आज औसत जीएसटी 11.5 फीसदी है।

कैट ने शादी के सीजन में 3.75 लाख करोड़ रुपये के व्यापार का जताया अनुमान

नई दिल्ली। दिपावली के त्योहारी सीजन में हुए जबरदस्त कारोबार से उत्साहित होकर दिल्ली सहित देशभर के व्यापारी अब शादी के सीजन की बिक्री में जुट गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शादी के सीजन में लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान जताया है। कारोबारी संगठन कैट ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि 4 नवंबर देव उठान एकादशी से 14 दिसंबर तक लगभग 40 दिनों के शादियों का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें देशभर में करीब 32 लाख शादियां होने का अनुमान है। इस सीजन में करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होना आंका जा रहा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में इस सीजन में लगभग 3.50 लाख से ज्यादा शादियों होने का अनुमान है, जिससे दिल्ली में ही करीब 75 हजार करोड़ रुपये के व्यापार की संभावना है। खंडेलवाल ने कहा कि पिछले वर्ष शादी के पहले चरण में देशभर में लगभग 25 लाख शादियां हुई थी, जिससे करीब 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार हुआ था। दरअसल यह आंकड़ां कैट की रिसर्च शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी ने हाल ही में देश के कुछ शहरों में व्यापारियों एवं सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच कराए गए एक सर्वे से लिया गया है। खंडेलवाल ने बताया की शादियों के सीजन से पहले घरों की मरम्मत, पेंट, फ़र्निशिंग, साज-सज्जा आदि का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। खासतौर पर ज्वेलरी, साड़ियां, लहंगे-चुन्नी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, फुटवियर, ग्रीटिंग कार्ड, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, फल, शादियों में इस्तेमाल होने वाला पूजा का सामान, फर्नीचर, किराना, गिफ्ट आइटम्स, खाद्यान, डेकोरेशन के आइटम्स, बिजली सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपहार में देने वाली अनेक वस्तुओं का व्यापार बड़े पैमाने पर हर साल होता है।

सीतारमण ने कहा- एनपीए कम करने के प्रयासों से सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा

- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों के परिणाम वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में बेहतर रहे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का मुनाफा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में सामूहिक रूप से 50 फीसदी बढ़कर 25,685 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज यानी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) को कम करने के सरकार के प्रयासों की वजह से ऐसा हुआ है।

सीतारमण ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि एनपीए को कम करने के प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि पीएसबी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफा में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर बढ़कर 25,685 करोड़ रुपये और पहली छमाही में बढ़कर 40,991 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस तरह इसमें क्रमशः 50 फीसदी और 31.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

सीतारमण ने एक के बाद कई सारे ट्वीट कर बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों के परिणाम वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में बेहतर रहे हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का मुनाफा 74 फीसदी बढ़कर 13,265 करोड़ रुपये, केनरा बैंक का शुद्ध लाभ 89 फीसदी बढ़कर 2,525 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह यूको बैंक का शुद्ध लाभ भी 145 फीसदी बढ़कर 504 करोड़ रुपये हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का मुनाफा 58.70 फीसदी बढ़कर 3,312.42 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों में से दो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) का मुनाफा नौ से लेकर 63 फीसी घटा है। डूबे कर्ज के लिए ऊंचे प्रावधान की वजह से इन बैंकों के मुनाफे में कमी आई है, लेकिन 10 अन्य सरकारी बैंकों का मुनाफा दूसरी तिमाही में 13 से लेकर 145 फीसदी बढ़ा है। दूसरी तिमाही में यूको बैंक के मुनाफे में सबसे ज्यादा 145 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लाभ 103 फीसदी बढ़ा है।

सहालग के चलते सोना 51 हजार के करीब पहुंचा, चांदी 60 हजार के पार

नई दिल्ली। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन आज सर्राफा बाजार में सोना और चांदी में तेजी का रुख नजर आया। शादी के सीजन की शुरुआत होने के साथ ही सर्राफा बाजार में तेजी के संकेत मिलने लगे हैं। आज की तेजी के कारण सोना 438 रुपये उछल कर 51 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर के करीब पहुंच गया है। चांदी ने भी 1,264 रुपये की तेजी के साथ 60 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार किया।

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक घरेलू सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट (999) सोने की औसत कीमत 438 रुपये की तेजी के साथ उछल कर 50,960 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थाई) हो गई। इसी तरह 23 कैरेट (995) सोने की कीमत भी 436 रुपये की बढ़त के साथ 50,756 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थाई) हो गई। जेवराती यानी 22 कैरेट (916) सोने की कीमत में आज 401 रुपये प्रति 10 ग्राम की मजबूती दर्ज की गई। इसके साथ ही 22 कैरेट सोना 46,679 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थाई) के स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा 18 कैरेट (750)

सोने की कीमत आज प्रति 10 ग्राम 328 रुपये चढ़ कर 38,220 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थाई) के स्तर पर पहुंच गई। 14 कैरेट (585) सोना आज 257 रुपये मजबूत होकर 29,812 रुपये प्रति 10 ग्राम (अस्थाई) के स्तर पर पहुंच गया।

सर्राफा बाजार में बनी तेजी के माहौल का असर चांदी की कीमत पर भी नजर आया, जो आज मजबूत होकर 60 हजार रुपये के स्तर से भी ऊपर पहुंच गई। आज के कारोबार में चांदी (999) में 1,264 रुपये प्रति किलोग्राम की उछाल दर्ज की गई। इस मजबूती के कारण ये चमकीली धातु आज उछल कर 60,019 रुपये प्रति किलोग्राम (अस्थाई) के स्तर पर पहुंच गई।

मार्केट एक्सपर्ट मयंक मोहन के मुताबिक शादी के सीजन की शुरुआत होने के कारण सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के गहनों की मांग में तेजी आई है। शादी के सीजन में आमतौर पर मांग बढ़ने की वजह से सोने और चांदी की कीमत में उछाल की स्थिति बनती है। ज्वेलर्स के लिए भी ये एक बड़ा कारोबारी मौका होता है। हालांकि मयंक मोहन का कहना है कि सर्राफा बाजार में आई मौजूदा तेजी की एकमात्र वजह शादी के सीजन के कारण बढ़ी मांग ही है।

उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी पर लगातार दबाव बना हुआ है। इसलिए शादी के सीजन के बावजूद प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियां बनने पर भारतीय सर्राफा बाजार में कभी भी गिरावट का रुख बन सकता है। सोने और चांदी के कारोबार में बनी वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक अभी भी बड़ा निवेश करने से बच रहे हैं। इसलिए जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की कीमत में स्थिरता नहीं आती है, तब तक छोटे निवेशकों को अपनी निवेश योजना काफी सोच समझकर बनानी चाहिए।

दक्षिण भारत को 11 नवंबर को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन

एनटीवी न्यूज

- चेन्नई और मैसूर के बीच वंदे भारत का ट्रायल रन संपन्न

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने सोमवार को चेन्नई के एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल ट्रायल रन किया। यह दक्षिण भारत के लिए पहली और देश की पांचवीं सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 नवंबर (शुक्रवार) को चेन्नई-बेंगलुरु-मैसुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्रेन के ट्रायल रन का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, "दक्षिण भारत की पहली वंदेभारत एक्सप्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहां एक्सप्रेस के ट्रायल रन की एक क्लिप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 नवंबर को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।"

हाई-स्पीड ट्रेन का बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायन्ना (केआरएस) स्टेशन पर सिंगल स्टॉप होगा। चेन्नई-मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करेगी और दोपहर 12:30 बजे मैसूर पहुंचेगी। रास्ते में यह 10:25 बजे बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायन्ना (केआरएस) स्टेशन पर पांच मिनट के लिए रूकेगी। वापसी में मैसूर से दोपहर 1.05 बजे ट्रेन रवाना होगी और शाम 7.35 बजे चेन्नई पहुंचेगी।

उल्लेखनीय है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूत उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में देश के प्रत्येक कोने को जोड़ने के लिए 75 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की थी।

मप्र में 27 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 15 जिलों के कलेक्टर बदले

भोपाल, । मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे दिन बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 27 अधिकारियों का तबादला करते हुए उनकी नवीन पदस्थापना की है। इस संबंध में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सोमवार देर रात आदेश जारी किया है। इससे पहले रविवार को भी 17 आईएएस अधिकारियों और 38 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया था।

राज्य सरकार ने सोमवार जिन 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, उनमें 15 जिलों -देवास, जबलपुर, इंदौर, उमरिया, सीधी, धार, सीहोर, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, सिंगरौली, मुरैना, आगर-मालवा, कटनी के कलेक्टर भी शामिल हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को औद्योगिक विकास निगम व मेट्रो रेल कार्पोरेशन का प्रबंध संचालक बनाया है। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी अब इंदौर के कलेक्टर होंगे। मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर का कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच को बनाया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को जबलपुर का कलेक्टर बनाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी को इंदौर, छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ सुमन को जबलपुर, बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह अढायच को सीहोर, कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को धार ट्रांसफर किया गया है, जबकि उज्जैन के अपर कलेक्टर अवि प्रसाद को कटनी कलेक्टर का दायित्व सौंपा गया है। सागर की अपर आयुक्त राजस्व शीतला पटले को छिंदवाड़ा कलेक्टर, सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ साकेत मामलीय को सीधी कलेक्टर, इंदौर स्मार्ट सिटी सीईओ ऋषभ गुप्ता को देवास कलेक्टर, भोपाल स्मार्ट सिटी सीईओ अंकित अस्थाना को मुरैना कलेक्टर, भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त ऋजु बाफना को नरसिंहपुर कलेक्टर और इंदौर नगर निगम की अपर आयुक्त भव्या मित्तल को बुरहानपुर कलेक्टर का जिम्मेदारी दी गई है। नगर प्रशासन विकास विभाग के अपर आयुक्त गौरव बैनल को भोपाल स्मार्ट सिटी सीईओ, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को एमपीआईडीसी एवं मेट्रो रेल कार्पोरेशन का एमडी, उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का सीईओ, देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को हाउसिंग बोर्ड आयुक्त, सीधी कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान को प्रशासन अकादमी में संचालक, धार कलेक्टर पंकज जैन को मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल का एमडी, सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को मप्र भवन विकास निगम का एमडी एवं पीसीबी में सदस्य सचिव बनाया गया है।

वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, बाल-बाल बचे ओवैसी

एनटीवी न्यूज

ओवैसी को किसी तरह की चोट नहीं लगी है। पार्टी के नेता वारिस पठान ने यह जानकारी दी

अहमदाबाद। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी सोमवार शाम जब अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे तो उनकी ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। वह वंदे भारत ट्रेन में सवार थे। जिस बोगी में वे बैठे थे उसी बोगी की कांच पर पत्थर लगा, जिससे शीशा टूट गया। हालांकि ओवैसी को किसी तरह की चोट नहीं लगी है। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि कई अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी कर कांच तोड़ दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।

इनसाइड

दतिया: श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी में गिरी, तीन की मौत, 21 घायल

दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोमवार देर शाम रतनगढ़ माता मंदिर पर जवारे चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सेवढ़ा सनकुआं के पास छोटे पुल से सिंध नदी में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 21 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। सभी मृतक दबोह लहार क्षेत्र के निवासी हैं। घायलों को उपचार के लिए दतिया जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय कुमार व सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस व प्रशासन की ओर से बचाव कार्य आरंभ किया गया। रात का समय होने से मौके पर बचाव कार्य में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा।

पुलिस के अनुसार दबोह के वार्ड क्रमांक 8 में रहने वाले कुशवाह परिवार की ओर से जवारे बोए गए थे। सोमवार को कुशवाह परिवार सदस्य आसपास के लोगों के साथ जवारों को चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर-टाली में सवार होकर रतनगढ़ माता मंदिर पर गए थे। माता मंदिर पर जवारे चढ़ाने के बाद सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान शाम को करीब 7.30 बजे सेवढ़ा सनकुआं सिंध नदी के पुराने छोटे पुल से गुजरते समय ट्रैक्टर-ट्राली का पहिया पुल के कटे हिस्से में फंस गया और वह अनियंत्रित हो गई और पुल में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ट्राली में सवार लोग चिल्लाने लगे। जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर गंभीर हालात को देखते हुए तत्काल आसपास से सभी जगह से 108 एंबुलेंस बुलाई गई। जिनकी मदद से पुलिस व प्रशासन ने घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा। आनन फानन में अस्पताल में घायलों के उपचार की व्यवस्था की गई। पुलिस के अनुसार, इस हादसे में जहां ट्रैक्टर ट्राली में सवार महिला ऊषा कुशवाह, कस्तूरी कुशवाह एवं गब्बर कुशवाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए, जिनमें महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी बताए गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यह बड़ा हादसा हुआ है। जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रात का समय होने से मौके पर बचाव कार्य में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री ने किया 8 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास

एनटीवी संवाददाता

भोपाल, । केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इच्छाशक्ति को विकास का मूलमंत्र बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना, परियोजना में क्या लागत आएगी, यह बड़ा सवाल नहीं है बल्कि इच्छाशक्ति का होना बहुत जरूरी है। आंखें दान दी जा सकती हैं लेकिन विकास की दृष्टि नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भागीरथ प्रयासों से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की सड़कें बनाई जाएंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के आग्रह पर जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क स्वीकृत करने की घोषणा की।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी सोमवार को जबलपुर में आयोजित सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4054 करोड़ की लागत से कुल 214 किमी. लम्बी आठ सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने आधा दर्जन मांगों को मंजूरी देते हुए विकास की नई सौगातें भी दी, जिसका लाभ दमोह, सागर, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिण्डोरी सहित समूचे मध्य भारत को मिलेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जबलपुर में विकास की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिये केन्द्र सरकार से हमेशा सहयोग मिलेगा। यहां शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार सहित अन्य सभी सेक्टर्स में विकास को गति मिलेगी। जबलपुर नगर में

एम्पायर टॉकीज से कटंगा, साउथ एवेन्यू मॉल से ग्वारी घाट-गुरुद्वारा तक रोप-वे को मंजूरी दी जा रही है। साथ ही सिविक सेंटर से मालवीय लार्डगंज, बड़ा फुहारा, बल्देव बाग तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होते ही फ्लाई ओवर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश में जहाँ कहीं भी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव देंगे, उन सबको मंजूरी दे दी जाएगी। शहपुरा-भिटोनी मार्ग को उन्नत करने और उमरिया-डुंगरिया मार्ग को रिंग रोड से जोड़ने के कार्य को स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा शहपुरा-नरसिंहपुर और दमोह की सभी सड़क परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप दिया जायेगा। जबलपुर में रिंग रोड पर तैयार होने वाले आईकॉनिक ब्रिज को पर्यटन के लिये विकसित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा सभी संभव मदद दी जाएगी।

गडकरी ने कहा कि जबलपुर से दमोह तक 800 करोड़ रुपये की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन सड़क निर्माण की मंजूरी दी गई है। इस मार्ग के लिये डीपीआर का कार्य पूरा हो गया है। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। जबलपुर के आईएसबीटी से पाटन तक 2 लेन सड़क, नरसिंहपुर से सिंहपुर तक 10 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क को मंजूरी दी गई है। नरसिंहपुर से श्योपुर मार्ग का डीपीआर बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर लंबा मार्ग नया एनएच होगा। बालाघाट से राजेगाँव तक 4 लेन मार्ग के लिये टेंडर प्रक्रिया वर्ष 2023 तक पूर्ण हो जायेगी। राजेगांव से रायपुर तक 3 हजार 500 करोड़ रुपये लागत से नया सड़क मार्ग तैयार किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि जबलपुर में बनने वाले रिंग रोड के आसपास की जमीन राज्य सरकार अधिग्रहित करे। डेव्हलपमेंट अथॉरिटी बनाये। इस जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क, इण्डस्ट्रियल क्लस्टर और स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा सकता है। भेड़ाघाट में म्यूजिकल फाउंटेन बनाने में केन्द्र सरकार मदद करेगी।

जबलपुर-नागपुर मेट्रो भी बहुत जल्द

गडकरी ने कहा कि जबलपुर और नागपुर के मध्य मेट्रो ट्रेन जल्दी ही शुरू की जायेगी। इसमें 8 बोगी होंगी। दो बोगी फल-सब्जियों के लिये रहेंगी। शेष छह बोगी में एक बिजनेस क्लास बोगी होगी, जिसमें हवाई जहाज की तरह सुविधाएं होंगी।

रिंग रोड जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सड़क परियोजनाओं-रिंग रोड का निर्माण जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। यह केवल रिंग रोड ही नहीं है, बल्कि युवाओं के रोजगार, उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विकास के लिये अनेक द्वार खोलने वाली परियोजना है। इससे महाकौशल क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जबलपुर प्रदेश के सर्वाधिक विकसित शहरों में होगा। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

चौहान ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने देश में विकास की नई परंपरा शुरू की है। उनकी कल्पनाशीलता का लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने असंभव को भी संभव बनाया है। अमृत फेज-दो में जबलपुर के लिये 720 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं। डुमना एयरपोर्ट 421 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। उन्होंने आईकॉनिक ब्रिज बनाने और मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिकतम बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों के विकास एवं जन-कल्याण संबंधी कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिये भेजे जाएंगे।

समारोह को केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव क्षेत्रीय सांसद राकेश सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

व्यक्ति को बेहतर योगदान के लिए प्रेरित करते हैं सार्वजनिक सम्मान : राज्यपाल पटेल

– रवीन्द्र भवन में हुआ गरिमामय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

एनटीवी संवाददाता

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सार्वजनिक सम्मान और पुरस्कार व्यक्ति को समाज में बेहतर योगदान के लिए प्रेरित करता है। उनका उत्साहवर्धन करता है। उन्होंने सभी सम्मानितों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे आगे भी वंचितों और पिछड़ों की मदद के लिए बेहतर कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल पटेल सोमवार शाम को भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित मप्र स्थापना दिवस के गरिमामय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के 40 जिलों के दूरस्थ अंचलों का भ्रमण कर चुके हैं। भ्रमण के दौरान वे वंचित और पिछड़े वर्ग के साथ सीधा संवाद करते हैं। सरकार की योजनाओं से मिलने वाली हितग्राहियों की खुशी की अभिव्यक्ति को देख कर उन्हें गर्व और हर्ष का अनुभव होता है कि वे उस प्रदेश के राज्यपाल हैं, जिसकी सरकार पूरी ताकत से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने सरकार द्वारा जन-कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी सरकार इसी गति से कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जन-कल्याण की योजनाएँ अंतिम कड़ी के व्यक्ति तक पहुँचाने में अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य के स्थापना दिवस पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि आयोजनों ने प्रदेश में उल्लास और उमंग का वातावरण बनाया है। राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान के लिए सम्मान और पुरस्कार की पहल प्रेरणादायी है।

प्रदेश के विकास के लिए मिलकर कदम बढ़ाएं: मुख्यमंत्री

समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए सभी मिल कर कदम बढ़ाएँ, हम प्रदेश की बेहतरी का संकल्प लें और आम इंसान को राहत देते हुए विकास के नए प्रतिमान स्थापित करें। विकास और शांति में खलल डालने वालों को छोड़ेंगे नहीं, नेस्तनाबूत करेंगे। वहीं अच्छा कार्य करने वाले निरंतर प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अनेक क्षेत्र में देश में अव्वल है। यह क्रम आगे भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कृत संस्थाओं और व्यक्तियों को बधाई दी। राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री चौहान ने विभिन्न श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए।

कार्यक्रम में मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, मंत्री सुरेश धाकड़, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, विधायक रामेश्वर शर्मा व कृष्णा गौर, भोपाल महापौर मालती राय और जिला पंचायत अध्यक्ष राम कुंवर गुर्जर मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह अंतर्गत भोपाल में सप्ताह भर चली विभिन्न गतिविधियों के प्रतिभागियों को भी प्रशस्ति-पत्र और ट्राफी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जबलपुर में 5 हजार करोड़ से अधिक राशि से सड़कों का जाल बिछाने के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और अन्य पुरस्कार देने का विचार काफी समय से मन में था जिसे आकर दिया गया है। यह सम्मान कार्य करने वालों के प्रति सामाजिक स्वीकृति है। यह सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं बल्कि उनके परिश्रम का सम्मान है। उत्कृष्टता और नवाचारों को सदैव प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य यही है कि अच्छा कार्य करने वाले और नहीं करने वाले एक समान न समझे जाएँ। उत्कृष्टता का सम्मान हो। पर्यावरण के क्षेत्र में, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले आज पुरस्कृत हुए हैं।

उन्होंने आहवान किया कि आज बिजली बचाने, पानी बचाने, नशा मुक्ति, पर्यावरण के संरक्षण, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने के लिए सभी मिल कर कार्य करें। मध्यप्रदेश को समृद्ध और गौरवशाली बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर और शक्तिशाली भारत के संकल्प को भी पूर्ण करें। मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में नंबर वन रहे, इसके लिए सभी सहयोग प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस उत्सव समारोह के समापन के अवसर पर प्रदेश में लगभग आठ हजार लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों में, जिनमें सामाजिक संगठन, बेहतर काम करने वाले कर्मचारी-अधिकारी, खिलाड़ी को आज सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अद्भुत है। वन-सम्पदा, जल-सम्पदा, जन सम्पदा ,कल-कल बहने वाली गंगा मैया की तरह